हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 19 मार्च, 1997

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11) 22
घोषणा —	
सचिव द्वारा	(11) 23
सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार करने संबंधी मामला उठाना	(11) 24
सदस्य का नाम लेना	(11) 28
वाक आउट	(11) 28
सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)	(11) 28
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(11) 29
समितियों की रिपोर्टस पेश करना	
(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 43वीं रिपोर्ट	(11) 29
(ii) सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 28वीं रिपोर्ट	(11)30
(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की 41वीं रिपोर्ट	(11) 30
बिल्ज-	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं०1) बिल, 1997	(11) 30
(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1997	(11) 47
वाक आउट	(11) 55
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं०2) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(11) 55
वाक आउट	(11) 59
दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं०2) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)	(11) 59

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Construction of P.W.D. (B & R) Rest House, Julana.

***239 Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a P.W.D. (B & R) Rest House at Julana (Jind) ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : No Sir.

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, जुलाना के लिए नहीं में क्यों जवाब आता है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है ? मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जुलाना में न तो सिंचाई विभाग का रैस्ट हाऊस है, न टूरिस्ट कंपलैक्स का रैस्ट हाऊस है और न ही पी०डब्ल्यू०डी० का रैस्ट हाऊस है। वहां आने वाले अतिथियों को काफी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सहानुभूति पूर्वक कोई जवाब दें जिससे कि वहां पर रैस्ट हाऊस बन सके।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1971 में जुलाना रैस्ट हाऊस के लिए सवा तीन लाख रु० का ऐस्टिमेट बना था। किसी कारणवश 1985 के अन्दर यह डैफर हो गया और उसके बाद उस पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन यदि अब लाठर साहब वहां के लिए पी०डब्ल्यू०डी० रैस्ट हाऊस आवश्यक समझते हैं तो इसके लिए वे लिखित रूप में दे दें, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : लाठर साहब, आप कितनी भी सप्लीमैंटरी पूछ लें लेकिन जवाब यही होगा।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने वहां पर कोई काम नहीं किया। इसलिए कम से कम चौधरी बंसी लाल जी के मुख्य मंत्रित्व काल में जिनको हरियाणा का निर्माता माना जाता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर विकास कार्य होगा।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने यह उत्तर नहीं दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बहादुरगढ़ सब-डिविजन में गांव जसौर खेड़ी और लहौर खेड़ी के बीच नहर का पुल टूटा पड़ा है। वह मेन रोड़ पर है। दो साल से इसके लिए मैटिरियल जैसे कि ईंटे वगैरह, वहां पर पड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि यह पुल कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न रैस्ट हाऊस से संबंधित नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी सब-डिविजन हैं, वहां पर पी०डब्ल्यू०डी० के रैस्ट हाऊस नहीं हैं। जैसे कि असंध सब-डिविजन में पी०डब्ल्यू०डी० रैस्ट हाऊस नहीं बना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर रैस्ट हाऊस बनाया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ के अंदर पी०डब्ल्यू०डी० रैस्ट हाऊस बहुत ही पुराना है। वहां पर कमरों की संख्या भी बहुत कम है। इस रैस्ट हाऊस की मरम्मत की भी आवश्यकता है। श्री राम बिलास शर्मा जी तो पावर में हैं, इसलिए ये तो कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। परन्तु मेरा प्रश्न पूछने का फर्ज बनता है कि इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर टेलीफोन भी नहीं है। इसलिए इनके प्रश्न पर गौर किया जाएगा।

Upgradation of Govt. Girls Middle School, Shekhupura Khalsa.

***233 Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government Middle School for girls of village Shekhupura Khalsa, District Karnal; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि घरौंडा ब्लाक के गांव शेखुपुरा खालसा के राजकीय कन्या विद्यालय को वर्ष 1990-91 में अपग्रेड किया गया था। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि यह जो उत्तर 'नहीं' में दिया गया है, इसके क्या कारण हैं। यह गांव काफी बड़ा है और वहां पर लड़कियों की संख्या भी काफी है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उस विद्यालय को दुबारा अपग्रेड करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा कि उस स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि उसके लिए कोई फाईनैंशियल एलोकेशन नहीं हुई। लेकिन अगर उसका दर्जा बढ़ाने के बारे में राजनैतिक दृष्टि से कोई बात हुई होगी तो उसका मुझे पता नहीं है। रिकार्ड में उस स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया गया था। हमने इस स्कूल का सर्वेक्षण करवाया था वह स्कूल अपग्रेडेशन के नार्म्ज पूरे नहीं करता। न उसके पास पूरी जमीन है और न कोई खेल का ग्राउंड है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप पहले नार्म्ज पूरा करें। उसके बाद उस स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए क्या-क्या नार्म्ज होने चाहिएं ? स्कूलों को अपग्रेड करने का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए कितने कमरे होने चाहिएं, कितने छात्र होने चाहिएं ? जो भी कंडीशन है वह मुझे बता दें हम वह पूरी कर देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने इस महान सदन में कई बार बताया है कि किसी स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 15 एकड़ जमीन चाहिए। पांच किलोमीटर की दूरी के हिसाब से कोई दूसरा स्कूल नहीं होना चाहिए और 14 कमरे चाहिएं। इस स्कूल के छात्रों की संख्या 583 है वह ठीक है लेकिन कमरे 13 हैं। मैं मोटे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जब वह स्कूल नार्म्ज पूरे कर लेगा, उसके बाद उसको अपग्रेड करने के बारे विचार किया जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नन्दरामपुर एक बहुत बड़ा गांव है। नन्दरामपुर स्कूल सारे नार्म्ज पूरे करता है। उसमें कमरे भी पूरे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी उस स्कूल में पढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं उस स्कूल में नहीं गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस स्कूल का दर्जा बढ़ाकर दस जमा दो प्रणाली का कब किया जाएगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, हम तो कैप्टन साहब की हर बात पर सदा से विचार करते आएं हैं क्योंकि इनके पिता श्री राव अभय सिंह जी हमारे संघ के वाइस प्रैजीडैंट होते थे इसलिए हम इनकी बात पर जरूर विचार करेंगे। आप उस स्कूल के बारे में हमारे पास लिख कर भेजें यदि वह स्कूल नार्म्ज पूरे करता है तो उसको अपग्रेड करने के बारे में विचार किया जाएगा।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, चिमनी के स्कूल में 19 कमरे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हाल है, कार्यालय कक्ष भी है और उसमें खेल के ग्राउंड की फैसेलिटी भी है। क्या उस स्कूल को कन्या हाई स्कूल का दर्जा देंगे ? मंत्री जी ने बताया कि स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ये ये नार्म्ज पूरे होने चाहिएं। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक डीघल कन्या हाई स्कूल है उस स्कूल की छात्र संख्या 1500 के करीब है क्या उस स्कूल को भी अपग्रेड करके दस जमा दो प्रणाली का बनाया जाएगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, डॉ० बीरेन्द्र पाल जी को बताना चाहता हूं कि डीघल रोहतक जिले का बहुत बड़ा गांव हैं। इन्होंने चिमनी के स्कूल के बारे में पूछा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए खास करके लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है। हम पूरे हरियाणा के अन्दर हर विद्यालय का सर्वेक्षण करवाएंगे और जो-जो स्कूल नार्म्ज पूरे करेगा उसको अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि कोई स्कूल नार्म्ज पूरे करता है और वह हमारे सर्वेक्षण में रह गया तो आप हमें उसके बारे में बताएं हम उसको अपग्रेड करने के बारे में विचार करेंगे।

श्री भागी राम : स्पीकर साहब, पिछली सरकार के पांच साल के दौरान जिन-जिन हल्कों में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुए क्या उन हल्कों के स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं अपने साथी चौधरी भागी राम जी को बताना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार जोकि एच०वी०पी० और बी०जे०पी० की सरकार है, स्कूल का दर्जा बढ़ाने में किसी तरह की राजनैतिक सोच नहीं रखती। हम पूरी तरह से पूरे हरियाणा का सामूहिक विकास करने की सोचते हैं। बच्चों को शिक्षित करने में हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे। जहां पर लड़कियों की संख्या अढ़ाई सौ होगी वहां पर हम स्कूल का दर्जा बढ़ाने में पीछे नहीं हटेंगे। जहां-जहां पर स्कूल अपग्रेड करने के नार्म्ज पूरे होते होंगे, वहां-वहां पर हम स्कूलों का दर्जा बढ़ा देंगे। इसलिए हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं।

Construction of New Roads

***264. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new road from village Ismaila to Chuliana and Ismaila to Kultana in Rohtak District; and

(b) if so, the time by which the said roads are likely to be constructed?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : (a) & (b)

There is proposal for construction of a road from Ismaila to Kultana which is likely to be completed by the end of 1998 subject to availability of funds. However there is no proposal to construct a new road from Ismaila to Chuliana.

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का आधा जवाब तो हां में दे दिया, इनकी मज़रें कुछ तो नर्म हुई मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इसमायला से कुलताना की जो सड़क है, वह कितनी लम्बी है और इस पर अब तक कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है और कब तक वह पूरी हो जायेगी ? दूसरी सड़क इसमायला से चुलाना के बारे में इन्होंने 'ना' में जवाब दिया है। मैं मंत्री जी से इस सड़क के बनाये जाने का भी आश्वासन चाहूंगा।

श्री धर्मबीर यादव : इसमायला से कुलताना तक की सड़क 1990 में सैंक्शन हुई थी। इस पर 18 लाख रुपये खर्च होने हैं। अभी इस पर एक किलोमीटर तक अर्थ बर्क हो चुका है। यह 5 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इस पर अभी तक 1 लाख रुपया खर्च हो चुका है। बाकी जैसे (फण्डज) अवेलेबल होंगे काम हो जायेगा। जहां तक इनकी दूसरी सड़क का सवाल है, उसकी अभी कोई परपोजल विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह गांव पहले ही किसी दूसरी सड़क से जुड़ा हुआ है और हमारे पास आलटरनेटीव रोड़ बनाने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि हमारे इलाके की सड़कें पीछे बाढ़ आने के कारण काफी टूट गई थीं। उनकी आज तक मुरम्मत नहीं हुई है। मंत्री जी मेरे हल्के के भागेश्वरी गांव में भी गये थे। उस सड़क की हालत इन्होंने देखी है। वहां पर पिछले 10 सालों से सड़कें की बिल्कुल रिपेयर नहीं हुई है। स्पीकर सर, वहां पर आपका इलाका भी पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तरफ ध्यान देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, मेरा भी सुझाव है कि सतपाल सिंह सांगवान ठीक कह रहे हैं कि 1995 में जब वहां पर भारी बाढ़ आई या लाई गई तब से तहसील दादरी में सड़कों की हालत बहुत खराब है

खासतौर पर जो लिंक रोड़ज़ हैं। उन सड़कों की रिपेयर बारे पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया और वे रिपेयर से वंचित रही हैं। क्या मंत्री जी इन सड़कों की रिपेयर करने का आश्वासन देंगे ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में भी इस बात का जिक्र किया गया था। मैं फिर बताना चाहता हूं कि जितनी भी सड़कें किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या सर्कल की टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर यह एच०वी०पी० व बी०जे०पी० की सरकार शीघ्र करेगी, चाहे वह किसी भी विधायक का क्षेत्र है।

श्री रामफल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि आने वाले वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नई सड़कें बनायी जाएं यानि मेरे कहने का मतलब है कि क्या हर क्षेत्र में 5-10 किलोमीटर की नई सड़कें बनायी जायेंगी या नहीं ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम लगातार ध्यान रखते हैं। जहां-जहां पर नई सड़कें बनाये जाने की आवश्यकता होती है वहां पर जरूरत के मुताबिक बनाते रहते हैं और आगे भी बनाएंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इनके चण्डीगढ़ के दफ्तर से जिला हैडक्वार्टरों पर कोई इस प्रकार की चिट्ठी गई है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कहीं पर भी कोई नई सड़क बनाने की कार्यवाही न की जाए और न ही कोई नई सड़क बनवाने के लिए कोई परपोज़ल ही बनाई जाए ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई है। विभिन्न नई सड़कें बनाने के लिए परपोज़ल्ज़ बराबर प्राप्त हो रही हैं।

Opening of P.H.C., Kulasi (Rohtak)

***352. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for Health be pleased to state the time by which the construction work of P.H.C., Kulasi (District Rohtak) is likely to be started/completed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : राष्ट्रीय नार्म्ज के अनुसार गाँव कुलासी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस गांव में पहले ही एक उप-केन्द्र कार्य कर रहा है।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने हाऊस में आश्वासन दिया है कि वहां पर एक उप-केन्द्र पहले से ही काम कर रहा है। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने के लिए 1989-90 में भवन निर्माण का कार्य 95% पूरा हो गया था और वहां पर अभी भी हैल्थ सैंटर ही काम कर रहा है। क्या मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर कब से काम करना शुरू कर देगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार इनके गांव की जनसंख्या 5 हज़ार से कुछ कम पड़ती है और इस समय छारा प्राईमरी हैल्थ सैंटर में यह गांव आता है। भारत सरकार की स्वास्थ्य नीति के अनुसार 30 हज़ार की आबादी के गांव में प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोला जाता है। इन्होंने बताया है कि इनके गांव में बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर यह कह रहे हैं तो वहां पर इस बारे में जांच करवा कर जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बिल्डिंग का 95% काम पूरा हुआ पड़ा है इसलिए मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि वहां पर यह सैंटर कब से काम करना शुरू कर देगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर बिल्डिंग कम्पलीट हुई तो जल्दी ही यह सेवा वहां पर शुरु करवा देंगे।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में बलियाना गांव में एक उप-केन्द्र है लेकिन बिल्डिंग नहीं है, क्या वहां पर ये बिल्डिंग बनवाने बारे विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो बिल्डिंगज़ बनाई हैं उनमें 25 पी०एच०सीज़०, 19 सी०एच०सीज़० और 10 होस्पीटल्ज़ आते हैं। जो गांव इन्होंने बताया है मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि वहां पर बिल्डिंग है या नहीं है अगर वहां पर बिल्डिंग नहीं है तो ये उसके बारे में दरख्वास्त भिजवा दें, इस बारे में स्थिति देख कर मैं इनको बता दूंगा। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि भूसला गांव में एक बहुत बड़ा होस्पीटल बनाया जा रहा है। यह होस्पीटल, एक छात्र कनाडा गया था वहां जा कर उसकी डैथ हो गई थी, उसकी याद में बनवाया जा रहा है। बड़ी हाई टैक्नोलोजी की मशीनें इस अस्पताल में इनस्टाल करने के लिए दिल्ली ऐयर पोर्ट पर आई पड़ी हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री तथा आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या वे इस मशीनरी को इस होस्पीटल में इनस्टाल करने के लिए दिल्ली से दिलवाने बारे कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक जिस अस्पताल के बारे माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, यह जिला कैथल में है। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले साल या डेढ़ साल से यह सामान दिल्ली ऐयर पोर्ट पर पड़ हुआ है और इस पर काफी डैमरेज भी पड़ रहा चुका है। उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती अगर उसमें कुछ एग्जम्पशन कोई दे सकती है तो वह सैन्टर गवर्नमैंट दे सकती है। इस बारे में ये मुझे मिले भी थे और मैंने इनको कहा था कि आप इस बारे में सैन्टर गवर्नमैंट से मिलें।

Repair of Roads

***302. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of District Rewari during the year 1996-97 :-

(i) Rewari-Sangwari road via Budhla Konsiawas;

(ii) Rewari-Assadpur road via Talanpur Istomrar Turkiwas;

(iii) Rewari-Nalhera road via Dakiva, Khatawali;

(iv) Approach road to Khayaliwas;

(v) Approach road to Jeetpura Pataudi, Rojka Kumsbewas, Gokulpur;

(vi) Approach road to Nand Rampur Bas, Bhastana;

(vii) Approach road to Kishangarh, Ghasora, Gindhokhar; and

(viii) Approach road to Jarthal, Sampli.

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Yes Sir, Road cuts have been filled. Further Patch Work and Premix carpet wherever necessary will be got done by 30-6-97 subject to availability of funds.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का तो यह पैट जवाब है कि फंड उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। जो सड़कें मैंने बताई हैं उनमें से खास तौर पर रिवाड़ी से संगवाड़ी तक की जो सड़क है उसमें इतनी ज्यादा खराबी आ चुकी है कि वहां पर 10 किलोमीटर से अबब भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह से रिवाड़ी से असदपुर तक की सड़क भी 30-30 फुट तक टूट चुकी है। इसके अलावा मंदरामपुर और घसौरा की जो सड़कें हैं। वहां पर पानी भरा रहता है। क्या इनको ये ठीक करवाने की कोशिश करेंगे? साथ में मंत्री जी यह भी बताएं कि इन पर कितना पैसा लगेगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन अजय सिंह तथा इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न में 8 सड़कों को मैंशन किया हुआ है और मैं 14 तारीख को इन 8 में से 6 सड़कों के बारे में जवाब दे चुका हूं। लेकिन कैप्टन अजय सिंह सदन का समय खराब कर रहे हैं। इन सड़कों की इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। इनको तो रात में भी सड़कों के सपने आते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, धारूहेड़ा से अलालपुर बाया बास एक सड़क है। यह मेरे गांव के पास है। 1995 में जब कैप्टन अजय सिंह जी मंत्री होते थे तो मैंने इनको कहा था कि इस सड़क का बहुत ही बुरा हाल है, यह सड़क टूटी पड़ी है। उस वक्त तो इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया लेकिन क्या आप इस बारे में कुछ करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इसको ठीक करवाएंगे।

Repair of Roads

***298. Shri Balbir Singh :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state the time by which the following damaged roads of Meham constituency are likely to be repaired:-

(i) Village Bhaini Bhairon to Meham;

(ii) Meham to Ballamba;

(iii) Meham to Ganganagar, Titri and Bhran;

(iv) Madina to Ajaib;

(v) Madina to Girawar;

(vi) Mokhra to Kalanaur; and

(vii) Mokhra to Muradpur Tekna and Lahli ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : इन सड़कों की पैच लगाकर मरम्मत कर दी गई है। बाकी मरम्मत का कार्य धन की उपलब्धता पर 30-6-1997 तक किए जाने की संभावना है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में कहा है कि मरम्मत कर दी गई है, यह इन्होंने इन सात सड़कों के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, महम हल्के में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है इसलिए वहां की सड़कें बर्बाद हो रही हैं। मंत्री जी कम से कम इन 6-7 सड़कों में किसी एक सड़क की मरम्मत तो करवा दें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, भैणी भैरो से महम रोड पर पैच वर्क किया जा चुका है। इसी तरह से महम से बहलम्बा, महम से भराण, मदीना से अजैब की सड़कों पर पैच वर्क किया जा चुका है लेकिन मदीना से गिरावड़ की सड़क पर काम होना अभी बाकी है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों पर यह काम हो गया है या अभी करवाया जाएगा ? मैं असलियत कह रहा हूं कि वे सड़कें बिल्कुल खराब हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो इन सड़कों के बारे में पड़ौसी हल्के के किसी विधायक से पूछ सकते हैं। मंत्री जी जितना काम करवा सकें, उतना ही हमें आश्वासन दें, ज्यादा आश्वासन हमें नहीं चाहिए।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि जैसे ही फंड्ज अवेलेबल होंगे, इन सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी।

श्री बन्तराम बाल्मीकी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वैश्चन लगा था जिसमें मंत्री जी ने गोडागुडी की जगह गोडागड़ी कर दिया यानी की ऊ की मात्रा हटा दी। ऐसा करके इन्होंने सारे सदन को गुमराह किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं। मंत्री जी ने एवं इनके औफिसर्ज ने हमारे को ही नहीं बल्कि सारे सदन को गुमराह किया है। इन्होंने कहा था कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो सड़कों से न जोड़ा गया हो तो मंत्री जी इस बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, यह कोई सप्लीमैंट्री नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पैच वर्क किस सड़क पर होता है ? जो सड़कें फ्लड में पूरी तरह से टूट गयी हैं तो क्या ये उन पर भी पैच वर्क करके काम चलाते हैं। महम के इलाके में मैं अभी थोड़े दिन यानी 15 दिन पहले गया था। आज से दो साल पहले जो फ्लड आया था तो उससे महम से लाखन माजरा वाली सड़क जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह आगे गोहाना से पानीपत को मिलाती है। आज इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। अगर आप पैच वर्क ही लगाते रहोगे तो आपकी सारी उम्र उस पर पैच वर्क करते ही निकल जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उसको दोबारा से बनाएंगे ? क्या आपने ऐसी सड़कों को आईडैन्टीफाईड किया है जिन पर पैच वर्क या मेजर वर्क की जरूरत है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, विभाग के अधिकारी असैस करके सड़कों का सर्वे करते हैं। जिन मौजूदा रोड्ज पर पैच वर्क होना है, उन पर पैच वर्क किया जाता है जो रोड्ज टूट गयी हैं, उनको दोबारा बनाया जाता है और जिन पर कारपेटिंग करनी होती है उन पर कारपेटिंग करते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : लेकिन क्या आपने ऐसी सड़कें आईडैंटीफाई की हैं ?

Loss suffered by Co-operative Sugar Mills

***319. Shri Jagbir Singh Malik :** Will the Minister for cooperation be pleased to state whether it is a fact that the cooperative Sugar Mills in the State running in losses during the last five years; if so, the yearwise details thereof together with the steps taken or proposed to be taken to make the aforesaid sugar Mills profitable ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : दस सहकारी चीनी मिलों में से सात सहकारी चीनी मिलें नामतः पानीपत, कैथल, महम, भूना, रोहतक, सोनीपत व शाहबाद पिछले पांच वर्षों में घाटे में रही हैं। इन मिलों के घाटे का विवरण तथा लाभ कमाने बारे किए गए उपाय संलग्न अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।

अनुबन्ध-I

पिछले 5 वर्षों में हुए घाटे के विवरण तथा लाभ कमाने बारे लिए गए उपायों का विवरण।

पिछले पांच वर्षों में सहकारी चीनी मिलों में हुए घाटे का विवरण निम्न प्रकार है :-

(रुपये लाखों में)
(अनुमानित)

मिल का नाम	1991-992	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
पानीपत	211.06	103.47	123.81	350.64	974.06
रोहतक	112.67	-	-	106.05	167.32
सोनीपत	-	-	-	-	173.31
कैथल	780.69	705.25	527.45	569.39	467.45
महम	675.64	347.13	127.87	01.38	568.75
भूना	557.27	828.48	710.09	802.76	951.51
शाहबाद	-	-	-	-	186.54

चीनी मिलों को लाभ की स्थिति में लाने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपाय

गन्ना प्रबन्धन

बेहतर गन्ना प्रबन्धन के लिए मिल्ज प्रशासन को सख्त किया गया है ताकि गन्ना बन्धीकरण, गन्ने का विकास तथा उच्च स्तर का गन्ना उपलब्ध हो सके। अधिक चीनी देने वाली किस्म के गन्ने की पैदावार का क्षेत्र बढ़ाने के लिए विशेषतः कैथल, भूना व महम मिलों में 'टिश्यू कल्चर टैकनोलोजी' का इस्तेमाल करने बारे कदम उठाए गए हैं।

मुरम्मत एवं रख-रखाव

मिलों की मुरम्मत एवं रख-रखाव सुनिश्चत करके विशेषतः शाहबाद, पानीपत, महम, कैथल व भूना मिल्ज की तकनीकी समस्याओं का निवारण कर अधिक चीनी उत्पादन सुनिश्चित किया गया है।

[श्री नरबीर सिंह]

वित्तिय सहायता

मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार ने चार चीनी मिलों को उनकी जरूरत पड़ने पर 3 करोड़ रुपए हिस्सा पूंजी तथा 2.00 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध करवाये गये हैं।

चीनी का निर्यात

इस पिराई सत्र से चीनी का निर्यात पहली बार शुरू किया गया है। जीन्द व करनाल मिलों ने चीनी के दो रैक निर्यात किए हैं तथा भविष्य में भी चीनी के निर्यात की सम्भावना है। ऐसा करने से चीनी के अधिक दाम मिलेंगे।

विक्रय वसूली

चीनी तथा अन्य सह उत्पादन विशेषकर शीरा की बेहतर विक्रय वसूली के लिए उचित अनुश्रवण किया गया है।

प्रबन्धन

मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबन्धन निदेशनों की लम्बी अवधि के लिए नियुक्ति सुनिश्चित की गई है जिससे बेहतर योजना एवं नियंत्रण किया जा सके।

विस्तारीकरण

गन्ने की अधिक मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पलवल व जीन्द मिलों के विस्तारीकरण का प्रस्ताव है जिससे मिलों को और लाभ होगा।

मिलों का पुनर्वास

कैथल, भूना तथा महम चीनी मिलों के बारे में पिराई क्षमता को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जनरेटिंग क्षमता को मिल चालू रखने के लिए पहले चरण में पुनर्वास प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन मिलों के घाटे में जाने के क्या कारण हैं और क्या इस बारे में कोई इंक्वायरी करायी गयी है या नहीं ?

श्री नरबीर सिंह : स्पीकर सर, जो तीन मिलें 1991 में लगीं थीं यानी भूना, कैथल और महम की शूगर मिल, उनमें इंक्वायरी करवायी गयी तो यह पाया गया कि इनकी मशीनें घटिया हैं। इसके अलावा भूना मिल में तो गन्ना भी उतना उपलब्ध नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए ये मिल्ज घाटे में हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि शाहबाद शूगर मिल जो पहले मुनाफे में थी और जिसका मुनाफा लगभग 35 करोड़ रुपये तक चला गया था लेकिन पिछले साल यह मिल डेढ़ करोड़ रुपये के लौस में आ गयी। इसमें जो गबन हुआ है उसकी जांच चल रही है। क्या उस जांच में कोई दोषी पाया गया है या नहीं अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

10.00 बजे **श्री नरबीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, शाहबाद मिल पिछली बार 1 करोड़ 86 लाख के घाटे में गयी। उसकी इंक्वायरी कराई गई है और एम०डी० को ससपैंड किया गया है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, पानीपत की शूगर मिल का जो घाटे का कारण है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। पिछले वर्षों में यह शूगर मिल बहुत घाटे मे रही है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पानीपत शूगर मिल सबसे पुराना मिल है इसको बने हुए 40 साल हो गए हैं इस मिल की इतनी पिराई की क्षमता नहीं है जितनी आज होनी चाहिए। इसलिए पानीपत शूगर मिल को शिफ्ट करने का प्रोग्राम है। गोहाना वाली शूगर मिल की गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से रिकमंडेशन आ गई है। पानीपत की शूगर मिल की भी जल्दी ही वहां से रिकमंडेशन आ जाएगी और इनको शिफ्ट किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अभी आपने फर्माया कि भूना शूगर मिल सबसे अधिक घाटे में रही और उसमें गन्ने की भी कमी है और बायबल नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मिल कब बनी थी क्या ऐक्सपर्ट कमेटी ने इसके बारे में कोई रिपोर्ट दी थी कि यह मिल बायबल नहीं हो सकेगी और क्या पहले यह रिक्वीजीशन थी कि गन्ना होना चाहिए।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस शूगर मिल की स्थापना 1988 में की गई और 1991 में यह बनकर तैयार हुई। 1991 से ही यह घाटे में चल रही है।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, महम, कैथल और भूना की मिलों के अंदर जो मशीनरी खरीदी गई थी उसके लिए क्या ऐक्सेस पेमेन्ट की गई थी, यदि की गई थी, तो क्या इस बारे में कार्यवाही हो रही है ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐक्सेस पेमेन्ट की गई है और उसके बारे में कार्यवाही चल रही है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिस सीजन में मिल चालू हुआ उसमें बायलर की एक ट्यूब 90 रुपये की पड़ती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

Shri Ram Bilas Sharma : Sir, this is question hour. Hon'ble Member can ask the question.

श्री बलबीर सिंह : सर, यह इससे संबंधित है। यह ट्यूब 90 रुपये में पड़ती है और इसका ठेका 450 रुपये प्रति ट्यूब के हिसाब से दिया गया। यह रिकार्ड की बात है। 705 ट्यूब डाले गए हैं। यह ठेका चन्द्र पाल सिंह ने लिया है और उसने दूसरे आदमी को 90 रुपये में यह ठेका दिया। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : इसकी पूरी जांच करा देंगे।

Widening of Dadri-Narwana/Rewari-Panipat Roads

***349. Shri Birender Singh :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen and widen the following roads :-

(i) Narnaul to Narwana via Dadri-Bhiwani & Jind; and

(ii) Rewari to Panipat via Jhajjar & Rohtak ?

Public works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Yes Sir.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें भी फंड की अवैलेबिलिटी वाली बात अड़ती है या नहीं ? क्योंकि यह तो मंत्री जी का जवाब बन चुका है। This is not proper on the part of the Minister because on every question he says whatever is to be done that depends upon the availability of funds. Atleast he should be categorical in his reply and he should not give the sweeping reply to the members. This is our right that we should get a categorical reply.

Mr. Speaker : Ch. Birender Singh, you please ask the question.

Sh. Birender Singh : But Sir, this is improper on the part of the Minister because every time he says that whatever work is to be done, will be done on the availability of funds. As for as this question relating to roads is cancerned, I want to know whether the roads from Narnaul to Narwana via Dadri, Bhiwani and Jind, Rewari to Panipat via Jhajjar and Rohtak will be constructed on the standard pattern of National Highway or not whether these will also be constructed the availability of funds. I think this point of availability of funds should not come in their way, because there is heavy traffic on these roads ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी वर्ल्ड बैंक से इस बारे में बातचीत चल रही है। कोटपुतली से नारनौल, नारनौल से महेन्द्रगढ़, महेन्द्रगढ़ से दादरी, दादरी से भिवानी, भिवानी से जींद और जींद से नरवाना तक सड़क बनाने के लिए तथा जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाड़ी से झज्जर, झज्जर से रोहतक, रोहतक से गोहाना और गोहाना से नरवाना की सड़क को भी बाईडनिंग करने के लिए वर्ल्ड बैंक से बातचीत चल रही है और फाईनेलाईज होने वाली है। हम जल्दी ही काम शुरू कर देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात और जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों से इन दोनों सड़कों पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया है क्या आपने इन दोनों सड़कों को नेशनल हाईवे में कंवर्ट करने के लिए भारत सरकार से कोई मामला या बात शुरू की है ? क्योंकि इन सड़कों पर अब जिस कदर ट्रैफिक बढ़ा है उसको देखते हुए अगर इनको नेशनल हाईवे में कंवर्ट कर दिया जाये तो इसके लिए आपको फण्ड भी भारत सरकार से मिलेंगे।

श्री बंसी लाल : भारत सरकार इन सड़कों को नेशनल हाईवे में कंवर्ट करने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने जो तरीका हमें सुझाया है हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। हरियाणा के अन्दर लगभग 872 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाई-वे के स्टेट्स की है जिनके बारे में वर्ल्ड बैंक से बातचीत चल रही है। इन पर 961 करोड़ रुपया खर्च होना है जिसका 70 प्रतिशत यानि 681 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक फाईनैंस करेगा और 30 प्रतिशत यानि 280 करोड़ रुपया स्टेट को खर्च करना है। वर्ल्ड बैंक ने पांच करोड़ रुपया इस स्कीम के तहत रिलीज कर दिया है जिससे अब सर्वे किया जा रहा है। एक डेविस कम्पनी मैसर्ज काल ब्रदर्स इस काम का सर्वे कर रही है। जैसे ही फण्डज एवेलेबल होंगे, कार्य शुरू कर दिया जायेगा जैसा कि मैंने पहले भी जवाब में बताया था जो तथ्यों के मुताबिक सही जवाब दिया गया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला-चण्डीगढ़ रोड पर आज काफी ट्रैफिक बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि यह रोड पंजाब राज्य के क्षेत्र से होकर आती है। इस सड़क पर हमारे एक माननीय सदस्य की सड़क हादसे में मृत्यु भी हो चुकी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे संबंधित सरकार से इस मार्ग को फोर लेनिंग में बदलने के लिए तथा डेराबस्सी के पास जो रेलवे फाटक इस मार्ग पर है, उस

पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की कोई बातचीत करने जा रहे हैं और अगर कोई बातचीत नहीं चल रही है तो आप क्या ऐसी कोई बातचीत करने का प्रयास करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का मामला तो कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन सड़क का बाया मीडिया यह है कि पंचकूला से शाहबाद वाया साहा एक नया रोड तैयार किया जाये जिसका स्टेट्स करीब-करीब नेशनल हाईवे जैसा हो। इसके बारे मामला विचाराधीन है और इस बारे भी वर्ल्ड बैंक ने ही फाईनेंस करना है जैसा कि अभी मैंने व्याख्या की है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जैसे रोहतक से पानीपत का रोड बनाया जा रहा है क्या ऐसा ही रोड सोनीपत का भी बनाने की कृपा करेंगे क्योंकि सोनीपत वाली सड़क की हालत बहुत खस्ता है कृपया मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी स्कीम के तहत रोहतक से सोनीपत (वाया गोहाना) को जोड़ने पर विचार किया जाएगा।

P.W.D. (B&R) Rest House, Ellenabad.

***386. Sh. Bhagi Ram :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a P.W.D. Rest House at Ellenabad in District Sirsa ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : हां श्रीमान् जी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि कम से कम इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब हां में तो दिया क्योंकि जब से हाऊस चल रहा है, इन्होंने हां में जवाब नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस रैस्ट हाउस का शिलान्यास कब हुआ, इस रैस्ट हाउस के शिलान्यास के बाद इस पर कितना पैसा खर्च हुआ, कब से इसका काम बन्द है और यह काम कब शुरू किया जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस भवन की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 1988 में हुई। जमीन मालिक ने हाई कोर्ट में इस बारे में एक पैटिशन फाईल की थी, जिसकी वजह से काम रूक गया था। हाई कोर्ट में सरकार जीत गई लेकिन उसके जमीन मालिक सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला 1990 में हो चुका है और उसके बाद 1994 में इसको बनाने के लिए कंट्रैक्टर से बात की गई तो उन्होंने उस रेट पर काम करने से मना कर दिया। अब दुबारा से इस का एस्टिमेट बनाने के लिए सरकार विचार कर रही है। अब तक इस पर लगभग 2 लाख 89 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, 1990 में सरकार यह केस जीत गई थी। 1990 से अब तक तो 7 साल का समय बीत गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसके ऊपर कब तक काम शुरू हो जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, 1990 में नहीं बल्कि 1994 में सरकार ने केस जीता था। 1990 में तो जमीन मालिक ने पैटिशन फाईल की थी तथा 1994 में यह केस सरकार के पक्ष में गया था।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर कोई रैस्ट हाउस नहीं है। अभी कल या परसों बाबू जी का वहां पर जाने का प्रोग्राम है। मेरे विधान सभा क्षेत्र इसनपुर में अभी कोई रैस्ट हाउस नहीं है। वहां पर जगह भी बहुत है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर एक रैस्ट हाउस बनवाने की कृपा करें ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, ये इस बारे में लिखित रूप में हमें दे दें। हम असैसमैंट कर लेंगे तथा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दादरी का जो रैस्ट हाऊस है, वह जींद रियासत के समय का बना हुआ है। वहां पर सिर्फ दो ही कमरे हैं। इन्होंने भी उसको देख रखा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उसकी भी एक्सपैंशन का कोई विचार है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

Production/Consumption of Liquor in the State.

***411. Shri Jagdish Nayar :** Will the Minister for Prohibition and Excise be pleased to state -

(a) the year-wise total consumption of Country liqiuor and Indian made foreign liquor (in proof litres) in the State during the years 1980-81 to 1995-96; and

(b) the year-wise & distillery-wise details of the Country liquor and Indian made foreign liquor produced (in proof litres) in the State during the period as referred in part (a) above ?

मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री (श्री गणेशी लाल) : विधान सभा के पटल पर ब्यौरा पेश है।

ब्यौरा

(क) वर्ष 1980-81 से 1995-96 के दौरान देशी शराब, बीयर सहित अंग्रेजी शराब की कुल वार्षिक खपत निम्न प्रकार है :-

वर्ष	देशी शराब (प्रूफ लिटर में)	अंग्रेजी शराब (प्रूफ लिटर में)	बीयर (बल्क लिटर में)
1980-81	49,93,664	44,43,067	57,21,755
1981-82	72,32,976	50,49,768	71,39,032
1982-83	80,05,330	54,32,743	62,61,948
1983-84	1,00,81,749	81,51,318	64,32,728
1984-85	1,19,97,430	77,84,723	82,44,445
1985-86	1,29,16,338	94,31,469	1,01,59,798
1986-87	1,34,85,708	1,12,44,918	86,86,941
1987-88	1,66,19,187	1,34,12,104	1,10,66,464
1988-89	1,87,52,696	1,36,72,159	1,96,88,826
1989-90	2,12,17,271	1,59,72,335	1,31,06,187
1990-91	2,38,54,788	1,79,82,875	1,59,00,936
1991-92	2,66,36,938	1,63,30,489	1,11,91,069
1992-93	2,87,03,526	1,83,71,962	1,26,02,363
1993-94	3,00,84,612	1,79,56,761	91,92,873
1994-95	3,10,73,144	1,84,97,378	97,87,197
1995-96	3,14,25,065	1,89,04,517	1,06,09,851

(ख) वर्ष 1980-81 से 1995-96 के दौरान देशी शराब तथा अंग्रेजी शराब के वर्षवार तथा मद्यशालावार उत्पादित आंकड़े (प्रूफ लिटर में) निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हरियाणा डिस्टलरी यमुनानगर		पानीपत डिस्टलरी पानीपत		एसोसिएटिड डिस्टलरीज लि० हिसार		अशोका डिस्टलरीज एण्ड केमीकल्ज (प्रा०) लि०, हथीन	
	देशी शराब	आई०एम०एफ०एल०	देशी शराब	आई०एम०एफ०एल०	देशी शराब	आई०एम०एफ०एल०	देशी शराब	आई०एम०एफ०एल०
1980-81	32,55,034	15,33,638	26,77,522	10,13,391	-	-	-	-
1981-82	48,72,367	23,67,174	27,22,513	7,95,256	-	-	-	-
1982-83	53,43,766	18,54,976	27,44,047	4,53,684	-	-	-	-
1983-84	63,22,050	21,12,833	42,21,089	4,29,346	-	-	-	-
1984-85	70,48,112	27,68,322	47,66,445	6,27,175	7,86,651	-	-	-
1985-86	66,03,557	24,64,851	38,84,344	12,92,753	34,24,773	-	-	-
1986-87	67,18,798	29,91,517	44,36,728	12,01,807	28,60,407	11,54,728	-	-
1987-88	92,13,044	24,47,092	52,59,088	9,25,820	18,40,699	17,05,241	-	-
1988-89	1,09,84,094	23,50,610	53,66,373	10,38,874	23,08,022	30,65,472	-	-
1989-90	1,17,31,930	27,18,913	57,27,312	12,87,289	34,76,924	28,96,188	-	-
1990-91	1,32,30,899	33,36,541	58,89,904	8,80,092	47,31,713	23,78,546	-	-
1991-92	1,32,62,307	32,52,889	58,94,584	8,43,368	67,95,905	16,90,014	14,16,967	3,43,238
1992-93	1,28,75,237	37,10,046	60,91,607	7,67,456	68,00,014	18,30,735	30,51,526	3,47,121
1993-94	1,30,80,940	44,63,866	56,93,177	5,79,077	69,27,519	20,18,547	41,96,512	9,69,464
1994-95	1,26,22,302	40,81,669	52,08,912	2,00,044	66,65,099	23,89,189	61,47,774	13,46,449
1995-96	1,46,75,985	40,65,869	46,29,596	-	64,55,716	29,72,645	57,29,098	14,03,907

[श्री गणेशी लाल]

वर्षवार तथा ब्रुवरीवार उत्पादित बीयर का विवरण

वर्ष	इन्डो लान ब्रा ब्रुवरी लि०, फरीदाबाद	हरियाणा ब्रुवरीज लि०, मुरथल (आंकड़े लाख बल्क लिटर में)	इनसिया इन्डस्ट्रीज लि०, जोनियावास (रिवाड़ी)
1980-81	55.74	55.30	
1981-82	61.97	50.24	
1982-83	71.39	44.02	इस ब्रुवरी का निर्माण वर्ष
1983-84	71.59	45.76	1992 में हुआ था तथा
1984-85	91.43	69.56	उत्पादन वर्ष 1993-94 के
1985-86	66.91	95.26	दौरान शुरू किया।
1986-87	80.99	93.34	
1987-88	80.32	73.93	
1988-89	104.97	65.23	
1989-90	107.59	80.65	
1990-91	123.10	75.78	
1991-92	125.40	77.10	
1992-93	132.93	89.23	
1993-94	151.81	79.75	33.77
1994-95	165.16	98.90	139.81
1995-96	168.74	115.36	212.01

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है लेकिन फिर भी इसमें दो ऐसे टैक्नीकल शब्द हैं- एक प्रूफ लीटर और एक बल्क लीटर। इसमें कंट्री लिकर के 3 लीटर 8 बोतल के बराबर होते हैं, आई०एम०एफ०एल० के 9 प्रूफ लीटर 16 लीटर के बराबर और 3 बीयर के बल्क लीटर 20 बोतल के बराबर होते हैं।

श्री जगदीश नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1996-97 में कुल कितनी खपत हुई ?

श्री गणेशी लाल : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने उन दो टैक्नीकल वर्डज को आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों के सामने क्लीयर करना चाहा था। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996-97 में लगभग 553 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के साथ लगभग 13 करोड़ 57 लाख शराब की बोतलें हरियाणा प्रदेश में कंज्यूम हुई। इन आंकड़ों को यहां पर जोड़ने के बाद 13 करोड़ 57 लाख नहीं बनते इसलिए मैंने प्रूफ लीटर और बल्क लीटर का जिक्र किया था। मैंने पहले जो आंकड़े आपको बताएं हैं यदि उनको मल्टीप्लाई करके ठीक करें तो जो हम सदन से बाहर प्रैस में और सदन के अन्दर कहते रहे हैं वह बिलकुल उनके साथ जुड़ जाएंगे।

श्री जगदीश नैय्यर : स्पीकर साहब, पिछली सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने जानबूझ कर उस रिकार्ड को खत्म तो नहीं कर दिया ?

श्री गणेशी लाल : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के 34930 ऑफैंस के केसिज हैं जो हमने पकड़े हैं। उसमें 13111 लोगों का चालान होने के पश्चात्, पिछली बार मैंने सदन में भी बताया था, लगभग 900 लोग कनविक्ट हो चुके हैं और लगभग 2 हजार 85 व्हीकल्ज को हमने इम्पाउंड किया है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक जुलाई 1996 से शराब बंद होने के बाद अब तक पुलिस द्वारा कितनी शराब पकड़ी गई और जो शराब पुलिस द्वारा पकड़ी गई क्या उसको नष्ट किया गया या और कुछ किया गया ?

श्री गणेशी लाल : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि शराब के मामले में जिनके केस डिसपोज औफ हो चुके हैं उस शराब के बारे में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी पढ़ा होगा कि उस शराब की होली सी जलाई गई। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया लेकिन अभी तक जिनके केस चल रहे हैं वह शराब गोदामों के अन्दर और रैस्ट हाउसिज के अन्दर पड़ी है। जहां तक यह सवाल है कि शराब की कितनी बोतलें पकड़ी गई उसकी फिग्गर मैंने सदन की टेबल पर रख दी हैं उनको आप जोड़ कर देख सकते हैं।

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि शराब को जला कर डिस्ट्रॉय करके नुक्सान करने की बजाय उसको दिल्ली, राजस्थान या किसी दूसरी स्टेट को बेच दिया जाए ताकि हमारी स्टेट की कुछ आमदनी हो सके।

श्री गणेशी लाल : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनका यह प्रश्न इस बैंच से शोभा नहीं देता बल्कि उस बैंच से शोभा देता है।

Digging of Harwa Gangoli Drain

***418. Shri Ram Phal Kundu :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the work of digging of Harwa Gangoli Drain from village Gangoli to Morkhi is likely to be started/completed ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Harwa Gangoli Drain is being surveyed for desilting. The drain is likely to be desilted before 30-6-97.

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हाड़वा गांगोली लिंक ड्रेन पड़ाना ड्रेन में जा कर मिलती है लेकिन पड़ाना ड्रेन में मिलने से पहले गांगोली और उन गांवों के एरिया के पास जो खरक, गागर एवं हाड़वा गांव लगते हैं वहां पर गांगोली और उन गांवों के एरिया के बीच में उसकी खुदाई नहीं की गई। उस ड्रेन का हिस्सा वहां पर ऊंचा है। उसकी वहां से खुदाई न करने के कारण पानी पीछे रुका रहता है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस नहर की पिछले साल गाद निकालने पर कितना पैसा खर्च किया गया था।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल का रिकार्ड तो इस समय मेरे पास नहीं है कि उस ड्रेन की गाद निकालने पर कितना पैसा खर्च किया गया। हम उसकी खुदाई कराएंगे ताकि जो पानी उल्टा बहता है वह आगे जाए। हम 30 जून से पहले इस काम को करा देंगे।

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैंने उस ड्रेन के बारे में रिटन में भी दिया था और महकमे वालों से रिक्वैस्ट भी की थी कि आप इस ड्रेन की खुदाई करा दें ताकि पानी आगे जा सके लेकिन महकमे वाले कहते हैं कि अगर खुदाई करा दें तो इसका लेवल पड़ाना ड्रेन के साथ नहीं मिलता है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, उसका लेवल मिलाने के लिए ही उसकी डीसिल्टिंग और खुदाई की जाएगी। अगर वहां पर और ज्यादा गड़बड़ मिलेगी तो हम उसको भी ठीक कराएंगे। 30 जून से पहले उस ड्रेन के पानी को आगे चलाने का काम कम्पलीट हो जाएगा।

Closure and Setting up of Industrial Units

***391. Sh. Jai Singh Rana :** Will the Minister for Industries be pleased to state the number of Industrial units that have been set up and closed separately, during the year 1996-97 in the district of Kurukshetra and Karnal ?—

उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता) : दिनांक 28-2-97 तक की सूचना निम्नानुसार है :-

	स्थापित इकाइयां	बन्द इकाइयां
कुरुक्षेत्र	196	2
करनाल	324	13

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इकाइयां बंद हुई हैं उनके बंद होने के क्या कारण है ?

श्री शशि पाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, इन इकाइयों के बंद होने के अनेक कारण हैं। कहीं पर तो कच्चे माल की कमी है, कहीं पर फाईनैंस की कमी है, कहीं पर भागीदारी की कमी है और कहीं पर मजदूरों की समस्या है। इन कारणों से ये इकाइयां बंद हैं। सरकार की वजह से इनको कोई तकलीफ नहीं है। सरकार तो हर तरह से इनको चलवाने के लिए तैयार रहती है।

तारांकित प्रश्न संख्या 395

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री रामजी लाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Panipat By-Pass

***406. Shri Om Parkash Jain :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state–

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a By-pass in Panipat; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Public Works Minister (Sh. Dharmvir Yadav) :

(a) Proposal for constructing a by-pass at panipat was referred to Ministry of Surface Transoport, Government of India but it has not been accepted so far.

(b) As the scheme is not yet sanction, no time frame for its completion can be given.

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो पानीपत में बाई पास बनाना था, वह अभी तक नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें पिछली सरकार के चहेतों की बिल्डिंग बीच में आ रही थी। वहां पर नैशनल हाई-वे होने से ट्रैफिक का काफी लोड है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस बाई पास को कब तक बना दिया जायेगा ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब तक बाई पास नहीं बन जाता तब तक सर्विस लेन कब तक बना दी जायेगी ?

श्री धर्मवीर यादव : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री राज कुमार सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब पंचकूला से यमुनानगर बाया शहजादपुर व सढ़ौरा जाते हैं तो उस सड़क पर रास्ते में एक पुल बनाया जाना बाकि रहता है। यदि वह बना दिया जाये तो वहां का 20 किलोमीटर का फासला कम हो सकता है। क्या मंत्री जी इस पुल को बनाये जाने पर कोई रोशनी डालने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि अभी तक इस तरह का कोई एस्टिमेंट पास नहीं हुआ है लेकिन यह मामला विचाराधीन है।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में हमारी एक भी सड़क की मरम्मत असल में नहीं हुई बल्कि वह मरम्मत सिर्फ कागजों में ही दिखाई गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, क्या उनकी मरम्मत कराई जायेगी ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, सभी सड़कों की मरम्मत की जायेगी चाहे वह किसी की भी हो। यदि कोई खास सड़क इनके नोटिस में हो तो हमें बता दें।

श्री कपूर चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शाहबाद शहर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि शाहबाद से बराड़ा की जो 18 किलोमीटर लम्बी सड़क है, वह पीछे बाढ़ के दौरान टूट गई थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सड़क को कब तक ठीक करने का इनका बिचार है ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे को ठीक रखना इस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारी सैकिण्ड प्रायरिटी फल्ड में जो सड़कें टूट गई थीं, उनकी रिपेयर की है चाहे वे किसी भी क्षेत्र की हैं और किसी भी दल से संबंध रखने वाले विधायक की हैं जैसे-जैसे पैसे मिलते जायेंगे, हम इनकी रिपेयर करते जायेंगे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि सांपला बाई पास रोड पर जहां बसें रूकती हैं, वहां पर यात्रियों के बैठने के लिए कोई शैड नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह शैड कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न परिवहन विभाग से संबंध रखता है। इस प्रश्न का भवन तथा सड़क निर्माण विभाग से कोई मतलब नहीं है।

Repair of Roads in the State

***400. Shri Ram Pal Majra** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the amount spent on the repair of roads in the state during the year 1996-97 ?

Public works Minister (Shri Dharamvir Yadav) : Sir, I would like to give the details of expenditure incurred on the repairs of roads during 1996-97.

Break up of expenditure on repair of roads during 1996-97 :

1.	**Out of budget allocation of the State :**		
	(a) For repairs like patch work, repair of berms, repair of bridges & culverts etc. on State Highways/Major Distt. Roads.	:	18.46 crores
	(b) For providing renewal coat on a length of 1303 Kms.	:	16.82 crores
2.	Repair of flood damaged roads out of Calamity Relief Fund provided by Govt. of India.	:	3.85 crores
3.	**Out of funds provided by Marketing Board :**		
	(a) For repairs like patch work, repairs of berms, repairs of bridges & culverts etc. on Link roads.	:	5.31 crores
	(b) For providing renewal coat on a length of 97 Kms.	:	2.01 crores
	Total	:	Rs. 46.45 crores

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी हर सवाल का जवाब लगभग यही देते हैं कि पैच वर्क का काम कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, गढ्ढे जो पड़े हुए होते हैं उनमें कुछ मिट्टी आदि डाल कर आपके हल्के में तो उन पर पत्ते डाल देते हैं लेकिन हमारे हल्के में तो वह भी नहीं डालते उसकी जगह पर पराली डाल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जो पैच वर्क का कार्य किया जाता है क्या वह पैच वर्क के नॉर्म्स के अनुसार करवाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जितना भी पैच वर्क किया जाता है वह निर्धारित नॉर्म्स के मुताबिक ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी डाल कर उसको छोड़ देते हैं।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जितनी भी सड़कों की मरम्मत की गई है या नई बनाई गई हैं क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये सारी की सारी सड़कें किस-किस जिले में और किस-किस हल्के में पड़ती हैं ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के लिए यह अलग से प्रश्न दें तो उसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ से सोनीपत जाने के लिए मुख्यत: दो मार्ग हैं एक तो बाया नाहरा-नाहरी और दूसरा आसोधा से हो कर है। इन दोनों ही मार्गों पर सिंगल रोड है। क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों को चौड़ा करवाए जाने बारे कोई आश्वासन देंगे ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जसोर खेड़ी का जो पुल टूटा हुआ है जिसका मैटीरियल भी वहां पर आया हुआ पड़ा है तो मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि यह पुल कब तक बनवा देंगे ?

श्री धर्मबीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि इस बारे लिखित रूप से ये प्रस्ताव भेजें। तब उसके खर्च की असैसमैंट की जाएगी और उसके बाद उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

Deaths due to Unknown Diesease

***422. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Health be pleased to state the number of deaths, if any, that occured due to Malaria/Jaundice/unknown disease in village Dhotar, district Sirsa, together with steps taken or proposed to be taken to prevent/control the said disease ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : पीलिया 'बी' (हैपाटाईटस 'बी') से गांव धौतर में 7 मौतें हुई। मलेरिया या किसी अन्य अज्ञात बीमारी से कोई मौत नहीं हुई। एक स्थाई चिकित्सा टीम गांव धौतर में स्थापित कर दी गई है। अतिरिक्त चिकित्सा तथा पैरा मैडीकल टीम इस क्षेत्र में लगा दी गई है। पीलिया 'बी' (हैपाटाईटस 'बी') का 20 व्यक्तियों को टीकाकरण किया गया है। 1029 रक्त पटिकाएं तैयार की गई। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा सरकार अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूर्ण रुप से साजो सामान सहित सुदृढ़ है।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को मैं धौतर गांव गया था। वहां पर ग्यारह आदमियों की मौत हुई है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने यह माना है कि वहां पर केवल 7 मौतें ही हुई हैं जबकि असल में वहां पर 11 मौतें हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर जो मौतें हुई हैं क्या वह घटिया पानी पीने के कारण हुई हैं या किसी और कारण से हुई हैं ? इसके साथ ही क्या मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो मौतें हुई हैं उनके परिवार के सदस्यों को एक्स-ग्रेशिया की कोई राशि दी गई है या नहीं और अगर नहीं दी गई है तो क्या कोई एक्स ग्रेशिया देने बारे सरकार विचार करेगी ? मरने वाले अधिकतर लोग हरिजन और गरीब पिछड़ी जाति के परिवारों से हैं।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, धौतर गांव में हुई मौतों के बारे में मैंने कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब में डिटेल से बता दिया था। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल 7 ही मौतें हुई हैं। सातवीं से आठवीं मौत नहीं हुई है। ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इन्हीं की अध्यक्षता में हाउस की कमेटी बना दें जो कि वहां पर जाकर खुद चैक करे और अगर सातवीं की जगह आठवीं मौत हुई हो तो हाउस मुझे जो भी सजा देगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इन्हें इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का एक ही धर्म है, हमारी सरकार मुख्यत: एक ही मुद्दा ले कर चल रही है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की जा सकती है। जहां तक एक्स ग्रेशिया का सवाल है तो विभिन्न जगहों पर कई प्रकार से मौतें हो जाती हैं और हर जगह एक्स ग्रेशिया देना सम्भव नहीं है इसलिए सरकार इस बारे फिलहाल कुछ नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन ऑवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Physical Verification of Afforestation works

***445. Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the minister of State for Forests be pleased to state whether any enquiry/physical verification in regard to the plantation works carried out by the Forest Department in district Hisar has been conducted by the conservator of Forests (Department) Panchkula during the year 1995-96, if so, the results thereof, together with the action, if any taken or proposed to be taken therof ?

Minister of State for Forest (Shri Jagdish Yadav) : Yes Sir.

A team of officers officials led by Conservator of Forests (Development), was deputed for undertaking the physical verification of plantation works executed by the Teritorial and Social Forestry Divisions in Hisar District in the year 1995-96. Their report claimed that 75 to 85 percent of the works undertaken in Hisar District was fictitious and held 89 persons including a Conservator of Forests and to Deputy conservator of Forests responsible for the mischief. However, the report was alleged to be suffering from malafide, personal prejudice, gross exaggeration, procedural irregularities and biased sampling by executing officers/officials. Even the officers deputed to assist accused the team leader of ignoring their cheking reports. Therefore, the Government has ordered that the conclusion of the enquiry may be got verified from a Senior Officer. An officer of the rank of Chief Conservator of forests has already been deputed for this purpose. Further action in this case will be taken on receipt of his report.

Provision of Pension to the Employees of Kurukshetra University

***447. Shri Ashok Kumar :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the pension scheme for the employees of Kurukshetra University, Kurukshetra, if so, the time by which the said scheme will be introduced ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : राज्य सरकार ने कुरुक्षेत्र विद्यालय को, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 1-4-95 से पैंशन योजना लागू करने बारे कुछेक शर्तों पर सहमति दे दी है। इस बारे विधियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Draining out Accumulated Flood Water

***373. Shri Virender Pal Ahlawat :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether it is a fact that flood waters have not been drained out so far from the vast areas of Village Gochhi and Seria of District Rohtak ; and

(b) if so, whether the aforesaid flood water is likely to be drained out before the next rainy season ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) yes,only two small pockets of 30 acres and 40 acres are still under flood water with depth varying from 3" to 9".

(b) Yes, since the depth of water is very less so, the dewatering at this stage is not possible. However, the standing water is likely to dry out by 15th April, 1997.

Extension of Khidwali Link Drain

***337. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the Khidwali Link Drain upto 'Agli Patti'; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) No Sir.

(b) The question does not arise.

घोषणा –

सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Now the Secretary will make announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bill which was passed by the Haryana Legislative Assembly during its November Session, 1996 and has since been assented to by the President.

[Secretary]

Statement

The Registration (Haryana Amendment) Bill, 1996.

सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनः विचार करने संबंधी मामला उठाना।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हम जो नये सदस्य यहां पर चुनकर आए हैं, हमने यह सोचा था कि यहां पर आने के बाद हम लीडर ऑफ दि हाउस से और प्रो० राम बिलास शर्मा से जो कि बहुत ही अच्छे पार्लियामैंटेरियन हैं, कुछ सीखेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में अगर सत्ता पक्ष में कुछ कमियां हों तो विपक्ष यहां पर उनको उजागर करता है और उसे करना भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे अपोजीशन के नेता और लैग खड़े हुए थे और मंत्री जी से उनकी बात हो रही थी लीडर ऑफ दि हाउस से उनका कोई झगड़ा नहीं था लेकिन उस वक्त आपने लीडर ऑफ दि अपोजीशन को सारे सैशन से निकाल दिया। इसी तरह से आपने चौधरी धीरपाल सिंह और रमेश खटक को भी सारे सैशन के लिए बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेता भजन लाल जी को भी सारे सैशन से बाहर निकाल दिया गया। मैं मानता हूं कि टोका टाकी होती है, नोक झोंक होती है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे और लीडर ऑफ दि हाउस से निवेदन करूंगा कि उनको सदन में वापिस बुला लें। लीडर ऑफ दि हाउस का जिस प्रकार से पहले रुतबा रहा है कि ये विरोधी पक्ष को सह नहीं सकते तो ये आज उसको छोड़कर के उस चैप्टर को खत्म करें। आपने जो मैम्बर्ज को और लीडर ऑफ दि अपोजीशन को सदन से पूरी कार्यवाही के लिए बाहर निकाला है उनको वापिस बुला लें । ऐसा करने से हम नौजवानों को भी अच्छी बात सीखने को मिलेगी । धन्यवाद ।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं । जो मेरे भाई राम पाल माजरा ने कहा है । कल जो कुछ भी यहां पर हुआ उसका हमें बहुत ही अफसोस है । उस वक्त हमें बहुत दुख हुआ । अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कस्टोडियन हैं, सर्वे सर्वा हैं ।अयक्ष महोदय, आपसे पहले यहां जो अध्यक्ष होते थे, एक बार उन्होंने मुझे अपनी कांस्टीचुएंसी में एजुकेशन से सम्बन्धित पुरस्कार बांटने के लिए बुलाया था । उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं आप लोगों के सहयोग से सी० एम० से भी चार फुट ऊपर बैठता हूं । जब मैं सी०एम० को बैठने के लिए कहता हूं तो वह बैठ जाता है और जब खड़े होने के लिए कहता हूं तो खड़ा हो जाता है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे में से जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं अगर वे ही हमारे बीच में न हों तो यह अच्छा नहीं लगता। चौधरी भजनलाल जी हों या चौटाला साहब हों, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है और खासतौर से लीडर ऑफ दी हाउस से भी मेरी रिक्वैस्ट है कि उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आज सारे हरियाणा के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं जो यहां यह हो रहा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि कल जो अनप्लेजैन्ट बातें यहां पर हुई हैं उनको भूल कर नया माहौल हमको शुरू करना चाहिए और जितने भी मैम्बर्ज कल आपने सस्पैन्ड किए हैं, उनको हाउस में बुलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी भी मेरी बात पर ध्यान दें कि गुड़गांव के अंदर आज एक दहशतगर्दी का माहौल हो गया है। पता नहीं आपके नोटिस में यह बात है या नहीं कि कल भी किसी एक आदमी का वहां पर कत्ल हो गया है और परसों भी एक आदमी का कत्ल करने की कोशिश की गयी। इसके अलावा 15 आदमियों को और ऐसे ही नोटिस मिले हैं कि अगर उनको दो-दो लाख रुपये नहीं मिले तो .....। (विघ्न) मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी को खत्म करवाएं। आज वहां पर एक दशहत सा माहौल फैल गया है।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, आज से एक साल पहले जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय जब हमारे नेता इस सदन में बैठकर सरकार को सुझाव दिया करते थे कि सरकार यह नीतियां लागू करे तो सजपा के ये भाई जो सदन में तो अपने आपको समता पार्टी का सदस्य मानते हैं और सदन के बाहर समाजवादी जनता पार्टी का सदस्य मानते हैं, कहा करते थे कि हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। लेकिन कल और परसों जो यहां पर हुआ, उसको यह सारा सदन और हरियाणा के लोग देख रहे हैं। जब कल माननीय दलाल साहब ने चौधरी भजन लाल जी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केस के संबंध में सफाई देने के लिए कहा तो उन्होंने बजाए सफाई देने के चौटाला साहब की पैरवी करनी शुरू कर दी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि अब आप ही बताएं कि ए और बी टीम कौन सी है और कौन किस की मदद कर रहा है ? आज सारे हरियाणा की जनता जानती है कि ये दोनों एक ही हैं दोनों ने ही मिलकर चुनाव भी लड़ा था। दोनों पार्टी रात को एक साथ बात करके सुबह यहां आती हैं फिर ये उस समय किस मुंह से कहते थे ? (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, यदि जीरो ऑवर में भी हमें आप बोलने का समय नहीं देंगे तो फिर हमारे यहां आने का क्या फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : आपको भी जीरो ऑवर में बोलने का समय मिलेगा। लेकिन उनको भी तो बोलने का अधिकार है। (विघ्न)

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, आपने तो बहुत ही दरियादिली से सबको बोलने का समय दिया है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का समय दें। कल भी आपने सारा समय ट्रैजरी बैंचिज के लोगों को ही दिया।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, यह रिकार्ड की बात है कि किसको कितना टाईम दिया गया है। इसलिए अब आप बैठे।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, आपने सत्ता पक्ष से भी ज्यादा समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया है लेकिन विपक्ष ने उस समय का दुरुपयोग ही किया है। जब तक हम इनकी बातों को सुनते रहे तब तक तो ये ठीक रहे और सरकार के ऊपर लांछन लगाते रहे लेकिन जब इनके सुनने की बारी आती है तो ये वाक आउट कर जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय जसविन्द्र सिंह जी से एवं उनके साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जीरो ऑवर में सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समान रूप से अधिकार है। इसलिए अब आप बैठें।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपको सबकी बातें सुननी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह जी, आप बैठें। आप और हम सब विपक्ष में ही थे भायना साहब, आप भी बैठ जाइए। मैंने पहले ही आपकी पार्टी से श्री रामपाल माजरा को बोलने का मौका दिया है।

श्री बलवंत सिंह : * * * *

श्री अध्यक्ष : बलवंत सिंह जी, जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनने की आदत नही है ये हमारी सरकार पर लांछन लगाते रहें और हम अपने कानों में उंगली डाल कर बैठे रहें तब तो ठीक है लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब देने का समय आता है तो ये वाक आउट कर जाते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने दो दिन पहले निवेदन किया था कि जो माननीय सदस्य चेयर की अनुमति के बगैर बोलेगा वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (शोर एवं विघ्न) सत नारायण जी, आप अपनी बात एक मिनट में कहें। बलवंत सिंह जी। आपको इनके बाद बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी से हमारे माननीय साथी श्री सतपाल सांगवान ने जवाब मांगा तो वे जवाब न दे सके। उन्होंने सदन को गुमराह किया कि भिवानी में 10 मौतें हुई हैं। उस बारे में जब उनसे नाम पूछे गए, इलाके पूछे गये तो वे दूसरी बातों में सदन को उलझाते रहे, सदन का समय बर्बाद करते रहे लेकिन आज तक उन्होंने वे नाम व इलाके नहीं बताए। किन लोगों ने इलाके बांट रखे हैं, यह सारे काम विपक्ष के लोग ही करते हैं। जहां तक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का सवाल है। आपने जो उन्हें यहां से निलम्बत किया है यह बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वह बार-बार सदन को गुमराह कर रहे थे उन्होंने सदन को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर गलत ब्यानबाजी की। मैं आपके द्वारा विपक्ष से कहना चाहूंगा कि इस सदन की कार्यवाई में विपक्ष अच्छे सुझाव दे जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हो। विपक्ष का काम यह नहीं होता कि हर बात में नुक्ता-चीनी करे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। इसलिए हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हाउस के अंदर जब भी विधान सभा का सैशन चलता है तो उसमें अपोजिशन का एक बहुत अहम रोल होता है। अपोजिशन अपने हल्के में जनता से जो बातें सुनता है, अगर वह बातें, वह समस्याएं जब सरकार के नोटिस में लाए तो सरकार को उससे भागना नहीं चाहिए। कुछ कमियां होती हैं वह बताई जाती हैं ताकि सरकार उनका सुधार कर सके। हमारी पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री धीर पाल सिंह, श्री रमेश कुमार खटक और कांग्रेस के चौधरी भजन लाल जी को जो यहां से निकाला गया है इससे हाउस में एक अजीब किस्म का सूनापन लगता है। अगर अपोजिशन न हो तो सैशन बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप कैबिनेट की मीटिंग बुला लें और सब कुछ पास कर लें। इसलिए मेरा आपसे नम्र शब्दों में अनुरोध है कि इन चारों को सदन की बाकी अवधि के लिए वापस बुला लिया जाए। मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी बैठे हैं उन्हें याद होगा कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार होती थी, उस समय यदि वे लोग कर्ण सिंह दलाल के साथ कोई गलत व्यवहार करते थे या उन्हें निकाला जाता था तो हमारी पार्टी उन्हें निकलने नहीं देती थी। जबकि आज ये हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। कोई भी सरकार यदि सिद्धांत के खिलाफ कुछ करती है तो हम उन लोगों की रक्षा करेंगे और उनका सहयोग देंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो शब्द उनकी तरफ से कहे गए हैं यह अच्छी परम्परा नहीं है। मैं फिर वही शब्द दोहराते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी धीरपाल, श्री रमेश खटक और चौधरी भजन लाल जी को यहां सदन में बुलवाया जाये ताकि इस सदन की परम्परा कायम रहे। गलतियां हो जाती हैं कोई खास बात तो नहीं हुई थी। ऐसा भी नहीं है कि चौधरी बंसीलाल जी के बारे में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई ऐसी बात कही हो। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी रहनुमाई में इस सदन की कार्यवाही पिछले दिनों से बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। मेरे विपक्ष के भाई जो यहां पर बैठे हुए हैं एवं प्रैस

गैलरी में जो प्रैस के भाई हैं वे और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आपने हमारे विपक्ष के भाईयों को खुद बोलने का समय दिया (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, सुनिये (विघ्न) मिस्टर भागीराम जी सुनिये। मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जो कुछ कहना है वह चेयर को एड्रैस करके कहें। विशेष रूप से भागीराम जी, आप तो बहुत पुराने सदस्य रहे हैं। आपको तो सुनने की जरूरत नहीं, आप तो सुनाने वाले हैं आप बोलते बहुत हैं (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यदि हमारे विपक्ष के सदस्य नहीं भी बोलना चाहते हैं तो उनको भी आप नाम लेकर बोलने के लिए खड़े करते हैं और आपके कहने के बावजूद भी कई सदस्य बोलना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, भाई रामपाल माजरा ने और आदरणीय गाबा जी ने ओम प्रकाश चौटाला और भजन लाल जी को वापस बुलाने के लिए कहा है क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में इनको सदन में उनकी कमी महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने बार-बार इनसे कहा है कि हम विपक्ष का आदर करते हैं आदरणीय विपक्षी भाईयों का आदर करते हैं इनमें से अगर कोई अच्छे सुझाव देना चाहते हैं तो हमें बताएं हम उन पर गौर करेंगे। लेकिन पिछले दिनों से आप ओम प्रकाश चौटाला जी का रवैया देखिये, वे किस तरह बार-बार खड़े होकर चेयर पर ऐशपर्शन करते हैं और किस तरह की कारगुजारी की बात करते हैं। भजन लाल जी, जो कई बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं, अगर आप चेयर से खड़े हो जाते हो तब भी भजन लाल जी बैठते नहीं थे और बोलते ही रहे। आपके बार-बार आग्रह करने के बाद भी वे अनापशनाप बोलते रहे। चौधरी भजन लाल जी ने आप पर भी छींटाकशी की है। मैं आपके माध्यम से भाई रामपाल माजरा और गाबा साहब को बताना चाहता हूं कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी भजन लाल जी ठीक बात करते हैं तो गलत बात करने वाला कौन है ? (विघ्न)

Mr. Speaker : No interruptions please.

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप पहले की कार्यवाही निकलवाईये। जब-जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी भजन लाल जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं तब-तब उन्होंने कभी कोई सुझाव नहीं दिये। हमेशा उल्ट-पुल्ट और अनाप-शनाप बातें की हैं। मायना साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब चौधरी भजन लाल जी हमें निकलवाया करते थे तो आपकी पार्टी के लोग बचाव के लिए आया करते थे। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यह बात देखी थी कि हमारी पार्टी के नेता और आज के मुख्य मंत्री उन दिनों जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो कभी उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ही उस समय की सरकार को अच्छे-अच्छे सुझाव दिये जो इस प्रदेश के हित में होते थे। चौधरी बंसी लाल जी जब भी बोलने के लिए खड़े होते थे ठीक बात बोलते थे। मैं भी जब खड़ा होता था तो ठीक बात करता था। लेकिन चौधरी भजन लाल जी जानबूझकर हमें तंग करने के लिए गलत तरीके से सदन से निकाला करते थे। यह सदन भी इस बात का गवाह है कि हमें न सिर्फ सदन से ही बाहर निकाला गया बल्कि हमारा अपमान भी किया गया। लेकिन कल जब वे सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे थे तथा अनाप-शनाप बातें कह रहे थे। (शोर) उसके बावजूद भी चौधरी भजन लाल यहां गैलरी में बैठकर बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे तथा सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन दिनों की आपको याद आनी चाहिए जब हमें सदन से निकाल दिया था और विधान सभा के गेट के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिये थे, जिन्होंने हमें विधान सभा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी तथा हमारा अपमान किया था। (शोर)

सदस्य का नाम लेना

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। * * *

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण लाल जी जो भी कह रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

(Despite the warning by the Chair, Shri Krishan Lal continued to speak and he did not resume his seat).

Mr. Speaker : I name Shri Krishan Lal. He may please leave the House.

वाक आउट

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आप हमें बोलने ही नहीं देते हैं तो हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से बाक आउट करते हैं।

(इस समय समता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

सदन के चार सदस्यों के निलम्बन पर पुनर्विचार करने सम्बन्धी मामला उठाना (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप देख ही रहे हैं कि ये लोग सदन की गरिमा का कितना सम्मान करते हैं ? जब ये बोल रहे थे तो हमने इनकी बात को पूरे गौर से सुना, हमने बीच में कोई रोका टोकी नहीं की। लेकिन इनके नेता भी यही काम करते हैं और अपने सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सिखाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बार-बार इनको बोलने का मौका दिए जाने के बावजूद भी इन लोगों का यह व्यवहार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कार्यवाही सदन में की गई है वह बिल्कुल उचित कार्यवाई है और इसको वापिस लेना बिल्कुल उचित नहीं है। (थंपिंग)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा का रिकार्ड है कि डिमांडज़ पर बोलने के लिए कल जितना समय दिया गया है, इतना समय विपक्ष को बोलने के लिए 1966 से 1997 तक कभी भी नहीं दिया गया। (थंपिंग) कांग्रेस पार्टी के 12 सदस्य कल डिमांडज़ पर बोले। उन्होंने 130 मिनट बोलने का समय लिया यानि 2 घंटे 10 मिनट बोले। अगर आज उनकी तरफ से यह कहा जाए कि उनको बोलने का समय नहीं दिया जाता तो सही बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने समय में विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए कितना समय दिया करते थे। समता पार्टी के केवल दो माननीय सदस्य बोले और उन्होंने 25 मिनट का समय लिया। इंडिपैंडेंट माननीय सदस्यों ने 57 मिनट बोलने का समय लिया। एच०वी०पी० का एक माननीय सदस्य केवल 14 मिनट बोला। टोटल 226 मिनट में से कांग्रेस पार्टी के सदस्य 130 मिनट बोले, 25 मिनट समता पार्टी के सदस्य बोले फिर भी यदि इनकी तरफ से यह लांछन लगाया जाए कि इनको बोलने का समय नहीं दिया जाता तो ठीक नहीं है। अगर आप यह चाहते हैं कि आप गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर कितना समय बोले और बजट पर कितना समय बोले तो गाबा साहब मैं वह समय भी बता सकता हूं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : मेरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य तो ऐसे कर रहे हैं जैसे स्पायल्ड चाईल्ड करता है। बच्चे को कहें की 5 रुपये ले लो तो वह कहेगा 10 रुपये लूंगा, उसको 10 रुपये देंगे तो वह कहेगा में 20 रुपये लूंगा और 20 रुपये देंगे तो कहेगा मैं 25 लूंगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है वह एक्सपंज होनी चाहिए।

Mr. Speaker : Please take your seat.

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Agricultural Minister (Shri Karan Singh Dalal) : Sir, I beg to move -

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 20th March,1997.

Mr. Speaker : Motion moved–

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 20th March, 1997.

श्री धर्मवीर गाबा (गुड़गांव) : स्पीकर साहब, रूल 30 के तहत कल के नॉन-ऑफिशियल-डे को ऑफिशियल डे में कनवर्ट करने के लिए मोशन आई है यह ठीक है कि कल के नॉन-ओफिशियल-डे को आप ओफिशियल-डे में कनवर्ट कर दें लेकिन मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या सैशन कल ही खत्म हो जाएगा या 21 तारीख तक चलेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, सैशन 21 तारीख तक बाकायदा चलेगा और अगर आप कहें तो हम सैशन आगे भी चला लेंगे। कल के नॉन-ओफिशियल-डे को ओफिशियल-डे में कन्वर्ट करने के बारे में फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हो चुका था। उस मीटिंग में चौधरी भजन लाल और ओम प्रकाश चौटाला शामिल थे।

Mr. Speaker : Question is -

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 20th March, 1997.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 43वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Ram Bhajan Aggarwal, Chairman, Committee on Public Accounts will present the Forty Third report of the Committee on Public Accounts for the year 1996-97, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1992-93.

Chairman, Committee on Public Accounts (Shri Ram Bhajan Aggarwal) : Sir, I beg to present the Forty Third Report of the Committee on Public Accounts for the year 1996-97, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1992-93.

(ii) सबोर्डिनेट लैजिसलेशन कमेटी की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now Shri Ram Bhajan Aggarwal, Chairman, Committee on Subordinate Legislation will present the Twenty Eighth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1996-97.

Chairman, Committee on Subordinate Legislation (Shri Ram Bhajan Aggarwal) : Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1996-97.

(iii) पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी की 41वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Satpal Sangwan, Chairman, Committee on Public Undertakings will present the Forty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1996-97 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1992-93 (Commercial).

Chairman, Committee on Public Undertakings (Shri Sat Pal Sangwan) : Sir, I beg to present the Forty First report of the Committee on Public undertakings for the year 1996-97 on the report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1992-93 (Commercial).

बिल्ज़ –

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill. He will also move the motion for its consideration.

11.00 बजे **Finance Minister** (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1997.

Sir, I also beg to move –

> That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved –

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव) : स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। मैंने जीरो आवर में भी बोलने की कोशिश की थी लेकिन आपने समय

देना ठीक नहीं समझा होगा। मेरी इस सरकार से आपके माध्यम से मोहतबाना गुजारिश इस एप्रोप्रिएशन बिल के जरिये है कि आज हमारे यहां पर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी यहां पर बताई जा रही है जितना नारा लगाया जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और होम मिनिस्टर से भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज पुलिस के पास गाड़ियों की काफी कमी है। आप देखिये कि यदि किसी थाने में 13-14 सिपाही हों और उस थाने के तहत 200 गांव आते हों तो वे सुरक्षा कैसे कर पाएंगे ? इन 13-14 सिपाहियों में से एक सिपाही तो कोर्ट में जाता रहता है एक दो संतरी लिखने में बैठे रहे और एक जीप चलाता हो तो वे क्या सुरक्षा कर पाएंगे ? स्पीकर साहब, 14 तारीख को सैशन के बाद जब हम गुड़गांव पहुंचे तो वहां पर 15 तारीख को एक फैक्टरी के मालिक को जबर्दस्ती जीप में डालने की कोशिश की गई। उस पर गोली चलाई गई। भगवान की कृपा से उसे गोली नहीं लगी। फिर उस पर तलवार से हमला किया गया। उसके बाद उस पर एक गोली और चलाई गई उसको मारने की कोशिश की गई और उसकी कार को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद तीसरी गोली फिर चलाई गई। देशी रिवाल्वर से गोली चलाई गई थी, वह किसी तरह से बच गया। अध्यक्ष महोदय, कल की घटना के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कल जब विधान सभा का सैशन खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मुझे एक टैलीफोन मिला कि एक डैलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता है। एक फैक्टरी के मालिक संजीव मलिक नई फैक्टरी के लिए कर्जा मंजूर हुआ था, वह कर्जा मंजूर होने के बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जाता है कि उसकी फैक्टरी ठीक चले लेकिन बाद में वह अपनी कार में मुर्दा पाया जाता है उसे गोली मार कर खत्म कर किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वहां पर 15 और इण्डस्ट्रीज के मालिकों को टैलीफोन आए हैं कि दिल्ली में डिलाईट सिनेमा के पास 2-2 लाख रुपये लेकर पहुंच जाएं नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो संजीव मलिक का हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी हालत में इंडस्ट्रीयलिस्ट के अन्दर अमनो-चैन कायम रह पायेगा, वे हिफाजत से रह पायेंगे ? स्पीकर साहब, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह शायद कुछ भाईयों को अच्छी न लगे। मैं कहना चाहता हूं कि 1991-95 के दौरान मैंने गुड़गांव हल्के की नुमाइन्दगी की है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 5 सालों में अगर एक इन्स्टांस भी ऐसा हुआ हो, जैसा अब हो रहा है, तो आप बता दें या इण्डस्ट्रीज में कोई डिस्प्यूट हुआ हो या किसी इण्डस्ट्रीलिस्ट को कत्ल करने की धमकी दी गई हो। इन 8-9 महीनों के अन्दर क्या हालत हुई है वह आप देख लें।

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय साथी गाबा साहब यह बता रहे थे कि गुड़गांव में पिछली सरकार के समय कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं गुड़गांव की बात इनको बताना चाहूंगा। (विघ्न) जो बात इन्होंने कही है मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। गाबा साहब कह रहे हैं कि इनके राज में 1991 से 1995 तक गुड़गांव में कोई धांधली या गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने स्वयं भले ही कोई गल्त काम न किया हो लेकिन इनकी सरकार के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल, उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदारी के लोगों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जे न किये हों। लोगों को डरा धमका कर जबरदस्ती गुण्डागर्दी के बल पर जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे करवाए गए। इनके मुख्य मंत्री और उनके परिवार के लोग हर प्रकार का गलत काम करते रहे हैं यह बात इनको भान लेनी चाहिए।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वहां पर कोई इण्डस्ट्रियल डिस्पयूट उस अरसे में नहीं हुआ है। किसी भी इण्डस्ट्री या फैक्टरी के मालिक को कोई धमकी कभी नहीं दी गई, किसी को कत्ल करने की धमकी नहीं दी गई। मैंने किसी जमीन के झगड़े होने के बारे में या और कोई

[श्री धर्मबीर गाबा]

ऐसी बात होने की बात नहीं कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आतंक और दहशत का माहौल आज गुड़गांव में है अगर यही हालात जारी रहे तो इण्डस्ट्रियल डिवैल्पमैंट नोएडा की तरह गुड़गांव में बिल्कुल बन्द हो जाएगी और वहां पर उद्योग धन्धे ठप्प हो जाएंगे। सरकार इसका कोई सोल्यूशन निकाले और वहां पर लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अर्ज करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रीज की सुरक्षा के अलावा भी फलोर ऑफ दि हाउस सरकार जो भी आश्वासन दे उसे पूरा करने का प्रयत्न करे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति को सम्भालिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी के खिलाफ धारा 200 लगा दी या किसी के खिलाफ 151 या 107 का केस बना कर उसे परेशान किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। आज आप बताईये कि कितने कत्ल के केसिज, कितने ब्राइबरी या डकैती के केसिज हुए ? क्या किसी का इस बारे में कोई पता लगा ? स्पीकर साहब, आप पिछले साल के और इस साल के आंकड़े मंगवा कर देख लें। अभी कर्ण सिंह दलाल जी बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि गुड़गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति अब बिल्कुल ठीक है ये पिछले साल के और हमारी सरकार के वक्त के आंकड़े मंगवाकर देख लें। पिछले महीने 10 लाख रुपये राजेन्द्र नामक व्यक्ति के लूट लिए गए और पंचायत ऑफिसर को किसी ने सड़क पर गोली मार दी। गोली मारने वाले पैदल आए लेकिन फिर भी बच कर निकल गए। इसके बावजूद क्या आज तक कत्ल करने वालों का कोई पता लगा ? अध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है यहां पर दावे के साथ बड़े नारे लगाए गए हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन आज गुड़गांव में इतनी दशहत फैल चुकी है कि शाम को छः बजे के बाद वहां पर बाजारों में और दूसरी जगहों पर कर्फ्यू जैसी हालत हो जाती है। पेरैंट्स अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से डरते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि पैसे के लिए उनके बच्चों का अपहरण कर लिया जाए। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई हालत है इसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एफ०आई०आर० लोज करवा दी जाती है कि यह साईट सलैक्शन गलत है लेकिन दूसरी ओर टी०ओ० उसे पास कर देता है, क्या यह कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ? इस बारे वर्तमान सरकार को सोचना है कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रकार की बातों के लिए जब हम लोग कहते हैं कि यह ठीक नहीं है तो हमें दबा दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता या कहा जाता है कि हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, हाउस में गलत बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ढंग से जो हकूमत चल रही है वह ठीक नहीं है और यह चलने वाली बात नहीं कि आप जो मर्जी आए, उसे हाउस में बैठ कर कर लें। आजकल लोगों को हर बात का पता रहता है। अध्यक्ष महोदय, प्रो० गणेशी लाल जी हमारे बहुत ही काबिल वज़ीर हैं। मैं एक बात उनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि फरवरी के महीने में जब डायरैक्टर, फूड एण्ड सप्लाईज़ डिपार्टमैंट के लोगों ने एक डिपो पर छापा मारा था तो 10 किलोग्राम आटे की थैली में से 500 ग्राम आटा कम निकला था। उसकी एफ०आई०आर० दर्ज है। डिपो वाला गरीब बहुत रोया कि आटा रात को ही मिल से आया है इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी गई। अध्यक्ष महोदय, वे मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि जब आटा मिल से आए तो उसे रोक लें और उन्होंने वैसा ही किया। अध्यक्ष महोदय, 1 हज़ार 10 बोरियां कैबिनो मिल से वहां पर आती हैं। जब उनको चैक किया गया तो उसमें 998 बोरियों में साढ़े पांच सौ से साढ़े 6 सौ ग्राम आटा कम मिला। अध्यक्ष महोदय, हमने उस मिल के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करने को कहा, हमने यह भी कहा कि अगर आप एफ०आई०आर०

दर्ज नहीं करेंगे तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। एक गरीब आदमी के खिलाफ तो फटाफट एफ०आई०आर० दर्ज कर ली जाती है और पैसे वाले के खिलाफ कुछ नहीं करा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एयर कंडिशन कमरों में बैठकर काम नहीं चलेगा बल्कि आज जरूरत इस बात की है कि आप ऐसे गलत काम नहीं होने दें। अध्यक्ष महोदय, आज आम आदमी बहुत मेहनत करता है और उसकी कड़ी मेहनत की ही पैदावार हमें मिलती है। आज गवर्नमैंट की ऐसी कोई पालिसी नहीं है जिसके तहत आम आदमी को कोई सुख मिला हो या लाभ मिला हो। आज किसानों को उसके गन्ने का पैसा नहीं मिला है। गुड़गांव में सड़के रिपेयर नहीं होती हैं। दलाल साहब से मैं यह कहना चाहूंगा वैसे मैंने इस बारे में इनको पहले भी कहा था कि ये ऐसा न कहें कि पिछली सरकार ने यह किया था वह किया था। दलाल साहब, अगर पिछली सरकार ने कुछ गलतियाँ की थीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उन गलतियों को दोहराएं। आपको तो ऐसा कहना चाहिए था और कहना चाहिए कि ये गलतियां हुई हैं और हम इनको सुधारने के लिए यह काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यहां का एक रैफरैंस देना चाहता हूं जब एक दिन मैं यहां पर बात कर रहा था कि राखी नाम की एक लड़की अपने स्कूल से छूट्टी के बाद घर आ रही थी तो उसे रास्ते से कार में उठा लिया गया और आज तक उस लड़की का पता नहीं चला तब यहीं से एक आवाज़ आई कि आप अपने समय के सुशीला कांड को भूल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर सुशीला नहीं मिली तो क्या उसकी आड़ में हम राखी को भी भूल जाएं उसको ढूंढने के लिए कुछ न करें ? हमें पिछली गलतियां ठीक करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिएं।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, गाबा साहब अब जो बात बोल रहे हैं, यह ये पहले भी बोल चुके हैं। इन्होंने बिल पर कोई और सुझाव या सुधार देना हो तो ही बोलें।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष पहले भी अनुरोध किया था और आज भी कहता हूं कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट और ईमानदार सरकार है। इसके लिए हमें कोई घुमंड भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, according to Dr. Ivor Jennings, the primary quilification that demands of a Government is honesty and transparency. अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आपके समक्ष यह निवेदन किया था कि हमारी सरकार एक ट्रांसपेरेंट सरकार है, ईमानदार सरकार है। हमारा धर्म है, कर्तव्य है। जैसे पंचायत के माध्यम से कम्पूटराईजेशन ऑफ सर्विसिज़ एस०एस० बोर्ड के माध्यम से आप जिसका भी 10 साल के बाद रिकार्ड चाहें चैक कर सकते हैं। यह सरकार सबकी सहमति के आधार पर चलती है। गाबा साहब ने जैसा कि अभी कहा कि डी०एफ०एस० सी० और डिपो के अन्दर शिकायत आई है कि फलानी मिल से जो आटा आता है वह वर्थ इटिंग नहीं है, वर्थ कंज्यूमिंग नहीं है और वह सेहत के लिए खराब है। लेकिन इनकी तरफ से मेरे नोटिस में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। अगर ऐसी जानकारी, जो ये कह रहे हैं, मेरे नोटिस में होती तो हम जरूर वहां रेड़ज मारते। हमने 5080 रेडज़ की हैं उनमें से 35 लोगों को पिंगालाईज भी किया है। बाकायदा उसका एक सिस्टम है। जिस प्रकार से यह सरकार ट्रांसपेरेंट है उसी प्रकार से ओपन मार्किट सेल्ज़ स्कीम के अन्तर्गत जो आटा आ रहा है उसे 19-12-1996 के पश्चात् स्टेट गवर्नमैंट ने नहीं बल्कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने ही एफ०सी०आई० को इंसिस्ट किया था कि जो लोग आपके वैटे हैं। या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पार्फत इस तरह की नकली कनक लोगों को सप्लाई करके जो ओपन मार्किट सेल्ज स्कीम के अंतर्गत आटा निकालते हैं, वह

[श्री गणेशी लाल]

खतरनाक है। 20-12-1996 को जब ओपन मार्किट सेल्ज स्कीम के अंतर्गत स्टेट गवर्नमैंट को अख्तियार मिला, उसके बाद हमने न केवल फेयर प्राईस शॉप्स के माध्यम से, डिपोज के माध्यम से आटा सप्लाई किया है बल्कि हमने तुरन्त इंस्ट्रक्शंज भी दी थीं कि वैन के ऊपर 61 और 64 रुपये के बीच की दस किलो की आटे की थैली रखकर गांवों के अंदर कहीं पर भी किसी भी बस्ती में जाकर उसका वितरण करें । लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पर कोई माल प्रैक्टिस किसी भी प्रकार की हुई है तो डी०एफ०एस०सी० को फोन करने का मतलब, डी०सी को फोन करने का मतलब मुझे यही लगता है * * * (विघ्न) मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा गाबा साहब से बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस के अंदर पिछले दो तीन दिनों से प्रजातंत्र की बातों पर बड़ी गहमा-गहमी चल रही है। यह ठीक है कि आप किसी भी बात के बारे में इंफ्रमेशन ला सकते हैं और उसके बारे में जानकारी लेने का आपका अधिकार भी है। आप उस बारे में पूछ सकते हैं। पर Can we afford the luxury to filirt with the sanctity of this august House. (Interruptions)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो काम ये खुद करते हैं, उसका औरों पर लांछन लगाने से इनकी गलतियों को दूर नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐप्रोप्रिएशन बिल पर सदन की सहमति हो और सदन में यह पास किया जाए तो सबकी सहमति तो आपको लेनी ही होगी। पिछले तीन दिन से सरकार ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं, पता नहीं इनके दिल और दिमाग में क्या बात है ? ये सोच रहे हैं कि अगर वोटिंग होगी तो पता नहीं क्या तुफान खड़ा हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप बैठें।

Shri Ganeshi Lal : Mr. speaker Sir, Mr. Birender Singh is the most learned and intelluctual member of the House.जिनको सुनकर मैं कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। बीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनता हूं। पहले भी मैंने आपकी हर बात सुनी है। I have listened you very patiently and consciously and regarded each and everything whatever you speak. (Interruptions)

Mr. Speaker : Birender Singh Ji, it is unfortunate that you have lost faith in me but I have full faith in you.

Shri Birender Singh : I still have faith in you, Sir.

श्री गणेशी लाल : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत नम्रतापूर्वक केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में इनम्मैच्योर इंफर्मेशन के आधार पर we should not create sensation. हम दो करोड़ जनता को मैसेज दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम 90 लोग यहां पर बैठे हैं और इन 90 लोगों के आप कस्टोडियन हैं। हम दो करोड़ जनता की बातें अपने माध्यम से यहां पर कहना चाहते हैं इसलिए इंफर्मेशन सीक करने का आपको अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रजातंत्र की बातें गाबा साहब ने भी, मायना साहब ने भी और धीरपाल सिंह जी ने भी जो कि इस समय हाउस में नहीं हैं, कही हैं कि प्रजातंत्र में हमको बोलने का अधिकार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर मैंने पढ़ा

है और जहां तक बीरेन्द्र सिंह जी जैसे मोस्ट इंटलैक्टुअल और लर्नड मैम्बर हैं वहां पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं। Liberty and equality are the two greatest pillars of democracy. (Interruptions)

बीरेन्द्र सिंह जी, आप मेरी बात एक मिनट के लिए सुन लें। आपका जितना भी भाषण होता है वह संसद के भाषण की तरह होता है। जब आप शिक्षा के ऊपर बोलें तो भी आप संसद के हिसाब से ही बोलें। अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट में ही अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि liberty and equality are inversly proportional, according to science and liberty without licence and equality without loss of equality are only possible in a system stemmed from Dharma, which is the only grarantee for constitutional morality and necessary checks and balances इसलिए जो ये बात करते हैं, वह ठीक नहीं है। यह तो हमारा धर्म बनता है, नीयत बनती है। Nobody till today in Haryana and in the country can question the integrity of the leader of the house as well as the Hon'ble Chief Minister of Haryana लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जो हमारे एक मोस्ट लर्नड मैम्बर हैं, ने कहा कि He is a man of steel. He is a developmental oriented man. जबकि गवर्नमैंट अपनी वर्किंग के मामले में पहले ट्रांसपेरेन्ट है लेकिन अगर इसके बाद भी कोई कहे तो अध्यक्ष महोदय, जो आपके पीछे खम्बे पर लिखा हुआ है, वह उनको बता दें। (विघ्न) मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि he cannot creat sanction. You have avoided untruthfulness, wrong statement delivered from the Opposition Benches. You have obliged them to go out of the House just to save from committing further sins in the House. Whatever this august House takes the decision, I have nothing to say about that. As far as the things are concerned, you have not taken a wrong decision. That is what I want to say.

Shri Birender Singh : Hon'ble Minister in an indirect way is passing adverse remarks/aspersion against the Chair. Why? Because this is yet to be decided whether the members of Opposition Benches who have staged a walk out was justified or not. What I want to say is that he is not supposed to preach the Chair because we know what we are to do. We know what is our function and what are our rights. You are to protect our rights, Sir, If this august House wants that the Appropriation Bill be passed then it should be with the consentand concurrence of the entire House and if should be passed in a systematic way. I must congtratulate the treasary benches the way they have scuttled the rights of the opposition Members in a systematic way. They have managed that six members should go out of the House. They were named by the Hon'ble Speaker because they created unruly senes and the Speaker had to give his ruling.

Mr. Speaker : It was the decision of the House.

Shri Birinder Singh : No, Sir.

Mr. Speaker : The Motion was moved and that was carried out.

Shri Birender Singh : It is very clear when you say that it was the sence of the House. If you have got the sence of the House that does not mean majority.

[Sh. Birender Singh]

unanimously and there is no dissention. So my submission is that if you want healthy democratic discussion and if you talk about equality and rights of the Legislature as well as two crore citizens of Haryana then the entire Opposition deserves to be heard. They should not go unheard, I want to say that the passing of the Appropriation Bill should be in a democratic manner. Sir, I would request you that you must reconsider it. I would like to say that the decision about the naming of the six Hon'ble Members must be reconsidered. Let the Leader of the opposition come here, Let the entire opposition be heard Let the leader of the Congress Legislature party be heard and then we should pass the Appropriation Bill, otherwise it would be the most undemoeratic thing.

Shri Ganeshi Lal : Sir, if they talk, it is love affair. If we talk, they call it a conspiracy.

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही है और एक मैंबर ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहा है, ला एण्ड आर्डर पर बोल रहा है, पब्लिक हैल्थ पर बोल रहा है लेकिन उसको बीच में रोक कर बीरेन्द्र सिंह जी ने वही कहना शुरु कर दिया जिसकी बिनाह पर पहले फैसला हो चुका है। जो कुछ फैसला हाऊस ने किया है वह फैसला फाइनल है वह फैसला स्पीकर साहब ने नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की इत्तलाह के लिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का टाईम इन्होंने अकेले ने 120 मिनट लिया है। अगर ये अकेले 120 मिनट बोलेंगे तो और सदस्य कैसे बोलेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला (भरवाना) : अध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल आपके समक्ष यह सरकार लाई है उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं विशेष तौर पर, जो आईटम पावर के मुताबिक मेजर हैड 2801 के तहत यह सरकार यहां पर लाई है, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। स्पीकर सर, बिजली हरियाणा प्रान्त की लाईफ लाईन है चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे डोमस्टिक सैक्टर हो, या कमर्शियल सैक्टर हो। पिछले नौ महीनों के अन्दर हरियाणा प्रान्त में बिजली की अवेलेब्लिटी में बड़ी भारी कमी आई है और हरियाणा की चहुमुखी प्रगति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। आज से नौ महीने पहले जब हरियाणा की जनता ने हविपा-भाजपा गठबन्धन सरकार को चुनकर भेजा था तो उस समय एक सबसे बड़ी बात हरियाणा की जनता के मन में यह थी कि चौधरी बंसी लाल शायद ऐसे व्यक्ति हैं कि जो वे बात कहते हैं वह करके दिखायेंगे। वे कहा करते थे कि अगर मेरी सरकार आई तो बिजली 24 घंटो में से 24 घंटे ही बिजली दिला कर दिखाऊंगा। इन्होंने यह भी कहा था कि किसानों को ट्यूबवैल के कनैक्शन 24 घंटे के अन्दर दिलाऊंगा। स्पीकर सर, पूरी बजट स्पीच, एप्रोप्रिएशन बिल और बजट की जो ग्रान्टस हैं उन सबको पढ़कर सिर्फ एक ही बात प्रतीत होती है कि चाहे हरियाणा में कृषि का क्षेत्र हो, गांव या शहर का क्षेत्र हो, सभी को मुश्किल से 24 घंटे में से चार घंटे भी बिजली ये मुहैया नहीं करवा पाये हैं। इसके साथ-साथ इस सरकार ने बिजली के उत्पादन के बारे में कोई नई स्कीम या कोई नया निर्णय नहीं लिया है। (विघ्न)

पिछली सरकार ने 6-7 नये प्रोजैक्ट हरियाणा में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए शुरू किये थे। मैं उनके बारे थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा। एक गैस बेसड प्लांट एन०टी०पी०सी० के साथ

400 मैगावाट का जो फरीदाबाद में लगाना था उसका पिछली सरकार ने एग्रीमैंट किया था। इसके साथ-साथ उड़ीसा सरकार ने एक हज़ार मैगावाट का पावर प्रोजैक्ट लगाने के लिए सी०ई०पी० हांगकांग की कम्पनी के साथ एग्रीमैंट किया था उसमें से 500 मैगावाट * * * * * (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, for your kind information.

यह एप्रोप्रिएशन बिल 1996-97 की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड का है। क्योंकि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं इसलिए I want to draw your attenion that whatever you may speak, you can speak on the supplementary demands for the year 1996-97 only. You are supposed to speak on the appropriation Bill pertaining to supplementary demands for the year 1996-97.

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : I would like to tell that all these agreements were entered in the year 1996-97, so I am referring to the year 1996-97 only Sir. इस तरह से जैसा कि अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि 500 मैगावाट पावर हरियाणा प्रांत को मिले जो एक हाई स्पीड मैगा पावर प्रोजैक्ट उड़ीसा सरकार ने सी०ई०पी०ए० जोकि हांगकांग की कम्पनी है से एग्रीमैन्ट किया था, उसके साथ पिछली सरकार ने, हरियाणा को 500 मैगावाट पावर के लिए हिस्सा दिया था। इसी प्रकार से 1200 मैगावाट पावर हरियाणा के लोगों को मिले, इस बात का मैमोरैंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग एक प्राईवेट फर्म के साथ साईन किया गया था। उसके तहत लिक्विड बैसड पावर स्टेशन लगाया जाना था। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो पानीपत थर्मल पावर प्रोजैक्ट की छठी यूनिट है, उसको चलाने के लिए भी पिछली सरकार ने फाईनल सुझाव दिये थे। इसी तरह से हिसार में एक हज़ार मैगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए कदम उठाया गया था। सिर्फ एम०ओ०यू० साईन होना बाकी था। पीछे चर्चा में यह भी कहा गया कि मैसर्ज यू०टी०आई० जो कि आइजनबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनीज, ईजराईल की है, उसके साथ पिछली कांग्रेस की सरकार ने बगैर मापदंडों को ध्यान में रखे एक एग्रीमैंट साईन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैसर्ज आईजनबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनीज ईजराइल एक रिप्यूटिड कम्पनी है जिस ने चीन के अंदर इंडस्ट्री सैक्टर में पावर प्रोजैक्ट्स लगाए हैं। इसलिए बगैर किसी जानकारी के सदन के अंदर कोई सूचना देना तथा यह कहना कि यह खिलौने बनाने वाली फैक्टरी है, शायद उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए और रिकार्ड भी ठीक रहे, इसके लिए आपके नोटिस में ला रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 7 या 8 पावर प्रोजैक्ट्स पर पिछली कांग्रेस की सरकार ने बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कार्य शुरू किया था और जो अलग-अलग स्टेज़िज पर था, दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा सरकार ने उनको पूरा करने के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया और न ही उन पर कार्य शुरू किया है। सिर्फ बुरी मंशा से बार-बार अलग-अलग पावर प्रोजैक्टस पर अलग-अलग बहाने से अलग-अलग तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। पिछली बार भी जब मैं इस सदन में बैठा था तो मैंने आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह कहा था कि हरियाणा सरकार ने जो लिक्विड बेस्ड पावर प्लांट लगाने के लिए एग्रीमैंट किया था, उसको सरकार जल्दी से जल्दी लगवाए। लेकिन आज 9 महीने के बाद मैं पाता हूं कि यह सरकार केवल इतना ही फैसला कर पाई है कि जो कांग्रेस की सरकार ने 1200 मैगावाट का प्लांट लगाने के लिए बिजली की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एम०ओ०यू० साईन किया था, वह ठीक था। वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में यह माना कि इस प्रकार के प्लांट जिन पर कांग्रेस सरकार ने कार्य शुरू किया था, वह हम पूरा करवाएंगे। (विघ्न) दलाल साहब, आप सदन में नहीं

[श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला]

थे, इसलिए आप बीच में इंट्रप्ट न करें। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा अहम् मुद्दा है, जो कि बिजली से रिलेटिड है तथा जिस पर आज की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम है कि पिछले 6 महीने के अंदर 3 बार नार्दन ग्रिड में पावर फेल्योर हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा के दक्षिणी भाग जैसे हिसार, सिरसा एवं जींद के इलाकों को कई दिन बगैर बिजली के रहना पड़ा। इसलिए यह जो बिजली की भारी कमी है, वह नार्दन ग्रिड को कंट्रोल न हो पाने के कारण है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा में जो हाईड्रो पावर है, उसका मुख्य सोर्स भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध के अंदर एक ऐसी घटना हुई लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस पर पंजाब तथा हरियाणा सरकारों का हिस्सा है। इन दोनों सरकारों ने आज तक इस घटना का कोई नोटिस नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की तरफ जरूर दिलाना चाहूंगा कि भाखड़ा बांध में हाई पावर हाउस के 5 जनरेटर हैं जिनकी क्षमता 132 मैगावाट की है। इस बारे में एक प्रोपोजल मूव किया गया था that in view of the availability of more water, let us increase its capacity to 150 megawatts so that the sharing States can get their larger share of the electricity produced. इसके लिए ड्राईंग और डिजाईनिंग संबंधी कार्यों की प्लेसमैंट हुई और प्लेसमैंट के बाद हर जनरेटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 9 माह की अवधि फिक्स कर दी गई लेकिन 9 माह की अवधि में एक जनरेटर को जुलाई, 1995 में बंद कर दिया गया। इसके मुताबिक मार्च, 1996 में उसका कार्य शुरू होना चाहिए था।

परन्तु 6 महीने की देरी हुई। उसके कारण जो शेयरिंग स्टेट्स हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से 54 करोड़ रुपये का बिजली की उत्पादन क्षमता का नुक्सान हुआ है। मैं मंत्री महोदय का खासतौर पर इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तब सरकार सोई पड़ी थी जब हरियाणा प्रान्त बिजली का अपना हिस्सा गवा रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब, एक रशियन कम्पनी को जिनके पास 135 मेगावाट से 150 मेगावाट बिजली करने का ठेका था, उसके बारे में भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड के अधिकारियों ने जिनमें हरियाणा प्रान्त के भी अधिकारी हैं, यह कहा कि ट्रांसफारमर का साइज छोटा कर देना चाहिए। रशियन कम्पनी को जब ट्रांसफारमर छोटा करने की प्रोपोजल दी गई तो उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफारमर को छोटा करने से इस पर जो यूनिट चलेगी वह ठीक नहीं चलेगी। उनके इस औब्जैक्शन के बावजूद उस ट्रांसफारमर का साइज छोटा कर दिया गया यानि वहां पर छोटे साइज का ट्रांसफारमर लगा दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर 132 मेगावाट की बजाय वह 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। जहां आप करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 132 से 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने चले थे उसका नतीजा यह हुआ कि वह 150 मेगावाट की बजाय 110 मेगावाट का हो गया यह एक बड़ा अहम् मुद्दा है। सरकार को अपने कानों में से रूई निकाल कर इस बारे में फौरन विचार करना चाहिए तथा इस बारे में भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड के अधिकारियों से मीटिंग करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए ताकि हरियाणा प्रान्त को बिजली का पूरा हिस्सा मिल सके। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली से ही संबंधित मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जब भाखड़ा में ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड बना, उस समय हरियाणा प्रान्त बिजली का अपना पूरा हिस्सा ड्रा नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय आपके बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम की कपैसिटी इतनी नहीं थी कि हरियाणा प्रान्त बिजली का पूरा हिस्सा ले सके। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसमिशन सिस्टम की इम्प्रूवमैंट के लिए पिछले 10 साल में जो प्रावधान किया गया है और आज की सरकार ने जिस बात का बीड़ा उठाया है जिसको हमने वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में पढ़ा है कि हम ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार

से यह भी जानना चाहूंगा कि with the improvement of the transmission system, will the Government also take effective steps, in order to get its share of electricity in the B.B.M.B. project becausae as on date you are not drawing your own share. You are drawing much less than of your share. डिप्टी स्पीकर साहब, एक बड़ी गम्भीर बात यह है कि अगर हरियाणा प्रान्त को हरियाणा प्रान्त की बिजली का पूरा हिस्सा मिलना शुरू हो जाए तो इस सरकार को पानीपत के थर्मल प्लांट में छठा यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है जिस पर 800 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। सरकार इस बारे में कारगर कदम उठाए। सरकार नया पैसा लेकर आने लग रही है लेकिन अगर आप उसको इस प्रकार बना लें कि हरियाणा प्रान्त की बिजली का जो हिस्सा है वह कानूनी है, वह जायज है और अगर आप वह सारा ड्रा कर लें तो फिर हरियाणा की बिजली की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बात की भी चर्चा की गई कि हरियाणा के अन्दर एक इन्डिपेंडेंट पावर रेगुलेटरी अथोरिटी बनाने की प्रपोजल है और हरियाणा प्रान्त के अलग-अलग जिलों को जोन्ज में बांट कर उस अथोरिटी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देने की प्रोपोजल है।

श्री मनी राम गोदारा : उनको दोनों सिस्टम नहीं देंगे, एक ही देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूसन दोनों सिस्टम देने का प्रोपोजल है। Production to a separate company Transmission and distribution to a separate company.

माननीय मुख्य मंत्री जी जब इन्टरवीन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि इसके लिए दो अलग-अलग कम्पनी बनाएंगे। उनमें एक स्टैच्यूटरी कम्पनी भी होगी लेकिन मुख्य मंत्री जी अपनी बात को अच्छी तरह क्लीयर नहीं कर पाए। इस सरकार की बजट स्पीच पर हाउस में डिस्कशन हुई और उसमें हाउस के नेता के बयान से ऐसा प्रतीत होता है और सरकार की यह मंशा है कि The production of electricity will be handed over to one company which will be statutority owned as the same project will be given to the assisted sector which will privately owned. In distribution and transmission, the State would be devided into four zones. In each of the four zones, districts will be handed over the system, which the State would develop उपाध्यक्ष महोदय, 1966 में जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा की जनता के मौलिक अधिकारों पर यदि कोई प्रहार होगा तो यह इन्डीपैन्डेंट पावर रैगुलेटरी अथोरिटी का प्रहार होगा। चौधरी जसवंत सिंह जी, आज इस सदन में मौजूद हैं जिन्होंने इस बारे में बड़ा साहसिक कदम उठाया। जब यह सरकार हरियाणा के किसानों, हरियाणा के व्यापारियों और आम आदमी के अधिकारों का एक प्राईवेट कम्पनी को बेचने की कोशिश कर रही थी तो इस व्यक्ति ने किसी बात की परवाह न करते हुए, अपने पद की परवाह न करते हुए और पद से मोह न रखते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया ताकि हरियाणा का किसान और आम आदमी जिन्दा रह सके। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बात के लिए उनकी ताईद करता हूं। जितनी उनकी तारीफ की जाय वह कम है। अगर हरियाणा प्रान्त के अन्दर एक इन्डीपैंडेंट पावर अथोरिटी बना दी गयी तो आपका पावर सिस्टम पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे वह किसी भी बिरादरी से संबंध रखता हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह कृषि वर्ग से सम्बन्धित हो, चाहे वह कमर्शियल वर्ग से हो या चाहे डैमेस्टिक पावर का संबंध हो, उसके रेट फिकसेशन की जिम्मेवारी आपके पास नहीं रहेगी। आपके पास हरियाणा के बिजली बोर्ड के सिस्टम का ट्रांसमिशन का, खंबों का, तारों का और ट्रांसफारमर्ज का कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह मैं पार्टी के या दलगत राजनीति की वजह से नहीं कह रहा। सवाल यह है कि आज हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम यहां इस सदन में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

की वजह से नहीं कह रहा। सवाल यह है कि आज हमारी यह जिम्मेवारी है कि हम यहां इस सदन में बैठकर हरियाणा की जनता को जवाबदेह हैं। आज की सरकार आज का पूरा विपक्ष और आज का प्रत्येक सदस्य, हरियाणा की जनता को जवाबदेह है। हमें जनता में वापिस जाकर यह बताना पड़ेगा कि वह संपत्ति जो हरियाणा की जनता ने 1966 से लेकर 1996 तक पब्लिक फंड से कई हजार करोड़ रुपये लेकर हरियाणा के अन्दर बनाई थी, उसका अब क्या कारण है कि उसको नीलाम करने की नौबत आई ? क्या कारण है कि आज सरकार के पास इतनी धनराशि क्यों नहीं कि वह उसको चला सके ? क्या ऐसा कारण है कि हरियाणा के लोगों के हक हकूकों को आज प्राईवेट आप्रेटरज को हरियाणा की सरकार नीलाम करने पर तुल आई है ? बिजली की दरें निर्धारित करने का फैसला आज सरकार के पास है, लेकिन वह अपने हकों को खुद किसी एक इन्डीपैन्डेंट पावर रैगूलेटरी को क्यों देने लगी है। . . . (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लयूड कर रहा हूं। आप घंटी बीच में न बजाया करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी खत्म करें, आपको बोलते हुए 18 मिनट हो गये हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डिप्टी स्पीकर साहब, आप मुझे 5 मिनट का समय दे दें। मैं जल्दी ही कनक्लयूड कर देता हूं आप बीच में घंटी बजाते हैं तो मेरी कन्ट्रेशन टूट जाती है। यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह बता रहा था कि सरकार को लोगों के हक हकूकों को एक इन्डीपैन्डेंट पावर रैगूलेटरी अथोरिटी को नहीं सौंपना चाहिए। यह हरियाणा की जनता के हित में नहीं है। मैं यह एक विपक्ष के सदस्य के तौर पर नहीं कह रहा बल्कि यह मैं इस सदन के सदस्य के तौर पर कह रहा हूं। सदन के हर सदस्य की यह जिम्मेवारी है कि सरकार की सम्पत्ति जो लोगों द्वारा टैक्स में दिए गए धन के द्वारा बनाई गई है, किसी प्राइवेट आदमी को मत बेचें। आप हरियाणा की जनता के साथ ऐसा अन्याय मत करें, नहीं तो हरियाणा के आम आदमी, हरियाणा के किसान आपको माफ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 4 जिलों की एक टैस्टिंग ग्राउंड बनाने का जो परपोजल है जिसमें अब भिवानी को भी शामिल कर लिया है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भिवानी हो, महेन्द्रगढ़ हो, जीन्द हो, हिसार हो, यह सब हरियाणा के ही हिस्से हैं। अगर यह स्कीम आप इतना बढ़िया समझते हैं तो इसको पूरे प्रान्त में लागू क्यों नहीं करते ? आप टैस्टिंग ग्राउंड 4 जिलों में क्यों बनाना चाहते हो ? इसलिए कृपा करके न हिसार को, न जीन्द को, न रोहतक को, न सोनीपत को, न महेन्द्रगढ़ को, न भिवानी को यानि हरियाणा के आम आदमी को हरियाणा की जनता को आपके द्वारा जो एक नया तुजर्बा किया जाने लग रहा है, जिससे हरियाणा के हक हकूकों पर सीधा असर पड़ता है, उसको आप एक टैस्टिंग ग्राउंड मत बनाईये। कृपा करके आप हरियाणा की जनता के हक में फैसला करिये, हरियाणा के किसानों के हक में फैसला करें। आप अपने हक किसी इन्डीपैन्डेंट पावर रैगुलेटरी अथोरिटी को मत दीजिए। बल्कि अपने हक खुद इस्तेमाल कीजिए। आज पूरी सबसिडी किसानों को देने की आपकी स्कीम नहीं है, पूरी सबसिडी हरियाणा के किसान को देने के लिए यह सरकार सक्षम नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह अपने खर्चों में कमी करके उस पैसे को जनता के विकास पर खर्च करे। इसके लिए जो वजीरों की फौज खड़ी की हुई है उसको कम करने की जरूरत है। मुख्य मन्त्री जी ने वजीरों की बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। इतने बड़े मन्त्री मण्डल से हरियाणा की जनता की भलाई किस प्रकार से हो सकती है, जनता को पूरी बिजली और पानी कैसे मिलेगा ? इसका प्रावधान आप बजट में करिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा। एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए जो पैसे का प्रावधान किया गया है उसके आंकड़े

है आज इन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। इनके लिए बजट में पैसे का अलग-अलग प्रावधान किया गया है। बजट में इनके लिए 27.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी प्रकार से हरियाणा हरिजन कल्याण निगम में 35.79 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, आई०आर०डी०पी० के तहत 7.70 करोड़ रुपये दिए गए हैं और इंदिरा आवास योजना के 8.11 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कुल मिला कर जो राशि हरिजन तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए रखी गई है वह 87.29 करोड़ रुपये बनती है। हरियाणा का पूर्ण स्टेट प्लान बजट 1575 करोड़ का है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप परसैंटेज के हिसाब से देखें तो वर्ष 1997-98 के बजट में कुल 5.54 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान इनके उत्थान के लिए रखा गया है (विघ्न)

डॉ० कमला वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि वर्ष 1997-98 के बजट के ये जो आंकड़े दे रहें हैं वह डिपार्टमैंटवाईज तो इन्होंने पढ़ दिए हैं लेकिन इस सारे बजट में एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्च होता है, उसका कोई उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। इनको कम्पैरेटिवली आंकड़ें दे कर अपनी बात कहनी चाहिए।

श्री मनी राम गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आनरेबल मैम्बर की जानकारी के लिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो टोटल बजट है वह करीब 1500 करोड़ रुपये का है इसमें से 90 करोड़ रुपये की राशि हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए रखी गई है। उसको ये सारे बजट से डिवाईड कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं और दूसरे खर्च भी आते हैं, उनको भी ये परसैंटेज के साथ लगाएं और फिर इन सारी फिर्गर्स को कम्पेयर करके देखें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस सैशन की कार्यवाही चल रही है आमतौर पर देखा गया है कि ये लोग अपनी बात तो कह लेते हैं लेकिन जब हमारी अपनी बात कहने की बारी आती है तो ये लोग सदन से वाकआउट करके चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सुरजेवाला साहेब ने जो फिर्ज सदन के सामने रखी हैं, वे हाउस को गुमराह करने वाली हैं। मैं आपके माध्यम से इनको कहूंगा कि ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश न करें। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपसे और भी कहूंगा कि ये जिन बातों का विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से एक बिजली के निजीकरण के बारे में भी इन्होंने कहा है। हमारी सरकार ने बिजली के सुधारीकरण का काम शुरू करने का निश्चय किया है। लेकिन जहां तक बिजली के निजीकरण की बात है वह तो इनकी पार्टी की हकूमत के समय से ही चली आ रही है। जो भी कान्ट्रैक्ट्स साईन हुए, वे इनकी पार्टी के राज के समय के ही हुए हैं। इनकी पार्टी के राज में जो भी काम होते थे वे गलत तरीके से होते थे और उनमें पैसे का लेन-देन होता था। वह बात आज किसी से छुपी हुई नहीं है। हरियाणा की जनता के साथ जो ज्यादती हुई और जो गलत काम इनकी सरकार के वक्त हुए, उनको आज तक हरियाणा प्रदेश की जनता रो रही है। भ्रष्टाचार की जो परम्पराएं इन्होंने अपने राज में कायम की हैं वह आज सब को मालूम है इसलिए इनकी अपनी बात को कहने से पहले सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह (नारनौंद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं माननीय मंत्री श्री कर्ण सिंह जी से कहना चाहूंगा कि यह जो सूर्जेवाला जी ने इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी अथोरिटी की बात कही है कि यह सरकार प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम उठा रही है, उसके फाउंडेशन स्टोन के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। वर्ल्ड बैंक और दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं इसमें सैन्टर गवर्नमैंट और हमारी सरकार भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी अथोरिटी को बिजली के क्षेत्र में लाना जरूरी

[श्री जसवंत सिंह]

भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी अथोरिटी को बिजली के क्षेत्र में लाना जरूरी नहीं है और यह किसानों, गरीबों और कंज्यूमर के हितों पर सीधा आघात है और प्रजातन्त्र की प्रणाली को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रहार है। यह सरकार खुद अपने हाथ कटवाने का प्रयास कर रही है। मैं सुर्जेवाला जी को बधाई देना चाहूंगा । मैं यह इसलिए नहीं कहता कि उन्होंने मेरी तारीफ की है बल्कि मैं उनको इसलिए बधाई दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेरिटी अथोरिटी के बारे में सत्य स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि वे इस प्राईवेटाइजेशन के सारे मामले में पुनः विचार करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं। यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप तो स्पीच देने लग गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) जसवन्त सिंह जी आप बैठ जाएं। अब करतार सिंह जी बोलेंगे।

श्री करतार सिंह भडाना (सफीदों) : उपाध्यक्ष महोदय, सुर्जेवाला जी काफी पढ़े लिखे हैं और हम तो अनपढ़ हैं लेकिन इन्होंने जो बताया कि भाखड़ा नहर में पानी की जितना हिस्सा हमारा है अगर हम उसको ही पूरा ले लें तो हमें कहीं से भी पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर ये बिजली के बारे में बोलते हैं कि यह सुधारीकरण ठीक नहीं है। मैंने इसी सदन में इनके मुंह से सुना था कि यह सरकार अच्छी है और अच्छा काम करेगी लेकिन आज ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी में विश्वास दिखाया था और आज ये उनके खिलाफ बात कर रहे हैं।(इस समय अध्यक्ष पदासीन हुए।)। स्पीकर सर, ऐसी क्या बात हो गई जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज हरियाणा में सड़के, बिजली और पानी किसने दिया है क्या इस बारे में ये जानते नहीं हैं क्या हरियाणा की जनता इस बारे में जानती नहीं ? इस बारे में सब जानते हैं कि यह सब कुछ बंसी लाल जी ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज इनके दिमाग में यह बात आ गई है कि अगर इस सरकार ने अच्छा काम कर दिया और बिजली की प्रोब्लम हल कर दी तो इनके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अगर यह सरकार अच्छे-अच्छे काम करती रही तो इनको यहां दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बार-बार यहां पर बिजली के प्राईवेटाइजेशन पर बोला जा रहा है। स्पीकर सर, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है इसलिए हो सकता है कि मैं गलत होऊं। जैसे पहले बैंक नेशनेलाइज किए गए थे। अगर अब कोई आदमी बैंक में जाता है तो उसको वहां पर इज्जत से बिठाया जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आप बैठें। आप तो पहले ही 28 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मुझे तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ने बिठा दिया था क्योंकि उस समय मंत्री महोदय इंटरवीन करना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी आप बैठें। आप हाई कोर्ट के वकील हैं और बहुत ही पढ़े लिखे हैं। इसलिए मैंने आपका ध्यान पहले भी आकृषित किया था कि आप जिस बिल पर बोलने जा रहे हैं वह 1996-97 का है। लेकिन अगला ऐप्रोप्रियेशन बिल आनेवाला है, अगर आप अपनी ये बात उस पर कहते तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि वह बिल 1995-96 का है। जब आपकी पार्टी की सरकार थी। लेकिन आप भटक गए।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : स्पीकर सर, मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं कोल एंड शकधर की बुक अपने साथ लाया हूं। अगर आप कहें तो मैं इस बारे में पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप जैसे विद्वान आदमियों का यह काम होना चाहिए कि वे गाईड करें। लेकिन अभी आप बैठें और भडाना जी को अपनी बात कहने दें।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे ये भाई शराबबंदी की भी बात करते हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे अपोजीशन के भाई बार-बार प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं ताकि इनका नाम भी पेपर में जरूर छप जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रेस गैलरी वाले तो हम सबके लिए एक समान ही हैं।

श्री करतार सिंह भडाना : अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये हमेशा उधर ही देखते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब सुर्जेवाला जी एक मिनट में अपनी बात कंक्लूड करें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : धन्यवाद सर, स्पीकर साहब, मैं यह चर्चा कर रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बिजली का जो निजीकरण है या जो पिछली सरकार ने पुराने पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनायी थी उनमें कोई त्रुटि थी।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से ऐप्रोप्रियेशन पर बोल रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, मैं पावर पर बोल रहा हूं। मैं उन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिनकी पिछली सरकार के समय में लगाने की योजना थी।

श्री अध्यक्ष : कब यह योजना थी ?

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, पैरा 33 में लिखा था—

"The Government has decided to revamp the power sector by moblizing resources from Private Sector for expension and modernisation of power system."

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही कंक्लूड करें।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : सर, जो आपकी क्वैरी थी तथा जो उस समय मांगे राम जी ने कहा था वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

"The reforms programme envisages segregation of power generation, transmission and distribution functions, creation of an independent power regulatory mechanism and participation of private sector in all the activities. The Haryana State Electricity Board has taken a number of steps to increase the generation capacity in the State. The State Government has signed a draft power purchase agreement with M/s U.D.I. a member of the isenberg Group of companies, Israel for setting up a 700 Megawatt Thermal Power Plant at Yamunanagar."

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, आपका समय समाप्त हो गया है अब आप बैठें।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर सुर्जेवाला जी बार-बार कह रहे हैं लेकिन मैने इनको कल भी एक बात कही थी कि जिस इलैक्ट्रिसिटी बिल की ये चर्चा कर रहे हैं जिस रैगुलेटिरी कमीशन की ये चर्चा कर रहे हैं This is not the proposal of the present Government. It was the proposal of the previous Government. We have drafted nothing about Electricity Board. यानी हमारी सरकार ने अभी तक भी इलैक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कोई ड्राफ्ट नहीं किया, कोई प्रपोज नहीं किया इसलिए इनको इरैलेवैन्ट बातें नहीं कहनी चाहिएं। इरैलेवैन्ट बातों के कोई भायने नहीं होते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप बैठें।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे रणदीप सिंह सुर्जेवाला को अपनी बात कहनी है क्योंकि फिर इन्होंने चले जाना है, ये तीसरी बार एक ही बात बोले हैं जिसका मैं जवाब देती हूं।

12.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** सुर्जेवाला जी जाने वाले नहीं है। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, इन्होंने नठ जाणा है, इन्होंने वापस नहीं आणा है।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, सुर्जेवाला जी बार-बार कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए पैसा बहुत कम रखा गया है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि जो भी स्टेट के अंदर बिजली, पानी सड़कें, ट्रांसपोर्ट हैं, उन सबके अंदर उनको हिस्सा दिया है 1996-97 में 12.4 प्रतिशत स्पैशल कंपौनेंट प्लान के अंदर खर्च किया गया है यानि 177.21 करोड़ रखा गया है। इस वर्ष भी ऐसे ही खर्च किया जाएगा, ऐसा मैं इनको आश्वासन देती हूं इसलिए ये अब 1.72 वाली बात न कहें। इन योजनाओं में कृषि, सहकारिता, फिशरी, पिगरी, बागवानी आते हैं, उन सब में यह सारा खर्च उन लोगों पर करने के लिए रखा गया है। यदि वह मिलाया जाए तो हो सकता है कि 12.4 % से भी ज्यादा हो जाए। जब हमारी योजना के अंदर 1430 या 1535 करोड़ रुपया हो गया है तो हरिजनों को भी पूरा हिस्सा उसमें से मिलेगा। मैं सुर्जेवाला जी से कहना चाहूंगी कि वे सदन और हरियाणा की जनता को बार-बार गुमराह न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भाई रणदीप सिंह सुर्जेवाला से आग्रह किया था कि वे पढ़े-लिखे जवान हैं और पहली दफा विधायक बनकर आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सदन को गुमराह करने वाली बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। वे अभी-अभी बोलते हुए कह रहे थे कि यह जो पानीपत का छठा यूनिट है इसके ऊपर 800 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इस यूनिट को ठीक करने के लिए टैन्डर वर्ष 1995 में मांगा गया था और औने-पौने भाव लगाकर हरियाणा की जनता के धन को लूटने के लिए यह टैंडर दिया गया था। हमारी सरकार ने आते ही कम से कम पैसों में इन यूनिटों में सुधार करने की चेष्टा की है। ये फिर यह भी कहने लगे कि बी०बी०एम०बी० से हरियाणा को उसका पूरा शेयर नहीं मिल रहा है इनकी यह बात भी सदन को गुमराह करने वाली है। हम हरियाणा का पूरा शेयर ले रहे हैं। इसके इलावा रोज की जो बिजली की खपत है, वह बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसके लिए हमको कम से कम एक लाख यूनिट पर डे के लिए ऐक्सट्रा बिजली चाहिए। इसलिए इन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (नारनौल) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे

बोलने के लिए समय दिया। मैं सबसे पहले सुर्जेवाला जी को बताना चाहता हूं कि वे मेरी तरह नये-नये विधायक चुनकर आए हैं। इसलिए शुरू-शुरू में तो अच्छी बातें कहें। अगर इन्होंने अभी से सदन को गुमराह करना शुरू कर दिया तो इनका अभी काफी लम्बा समय है। जनता इनका बहुत ध्यान रखेगी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हरियाणा की जितनी भी समस्याएं थीं, उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा अध्ययन करके एक-एक पहलू को छूकर यह बजट पेश किया गया है। इस बजट में हरियाणा के सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जितना बड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है उतना किसी सरकार ने नहीं उठाया। आप शराब बंदी को ही ले लीजिए। जिस राज्य का रोजाना दो करोड़ की शाम तक हानि हो तो ऐसा कौन होगा जो इस हानि को सहन करेगा और इस कार्य को करेगा ? लेकिन हरियाणा की भावी पीढ़ी में सुधार लाने के लिए, भारतीय संस्कृति को धर्म के अनुरूप चलाने के लिए इस सरकार ने जो मदिरा पान यहां से खत्म किया है, समाप्त किया है उसके लिए इन सबको मिलकर सहयोग देना चाहिये। इससे आने वाले समय में जैसा कि जो त्यौहार शादियां होती थीं उनमें जो धन हानि और जन हानि होती थी वह अब नहीं होगी। यह सब हमारे यहां आंकड़े मौजूद हैं उनसे मालूम होता है कि हर प्रकार के क्राईम में कमी आई है इस सरकार की सफलता का यह सबसे पहला उदाहरण है जोकि इन नौ महीनों में आपके सामने है। इस तरह से जो भी विभाग है खासतौर से आजकल बिजली विभाग के ऊपर चर्चा चल रही है, उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें जो कर्मचारी भाई काम करने वाले हैं, उनकी जो निष्क्रियता है जो काम करने की शक्ति है, उसमें जो कमी आई है, उसको ध्यान में रखते हुये कोई न कोई उपाय करना जरूरी हो गया था। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम प्राईवेट रूप से उसका ठेका देते हैं जैसे कि जयपुर-दिल्ली नेशनल हाई-वे का ठेका बिरला जी के पास है। वहां पर कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। और वे उसको समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर यह ठेका सरकार के पास होता तो उसमें सिर्फ 8 घंटे काम करके अपने घर जाने की हरेक कर्मचारी सोचता है। यह प्रैक्टिकल बात है। हमने देखा है कि किसी गांव में किसी घर की शिकायत आती है कि वहां पर वाटर सप्लाई विभाग के कर्मचारी पानी के लिए मोटर सिर्फ एक घंटा चलाते हैं जिससे पानी की ठीक से आपूर्ति नहीं हो पाती। इसी तरह से बिजली विभाग की कोई शिकायतें आती हैं गांवों में दो-तीन कर्मचारी जाते हैं और सिर्फ एक तार को ज्वायंट करके वापस आ जाते हैं जबकि उन दो-तीन कर्मचारियों कि तनख्वाह एक दिन की 250 रुपये बन जाती है। सिर्फ एक बिजली का तार जोड़ने के लिए अगर यह काम प्राईवेट व्यक्ति से करवाते हैं तो 50 रुपये में वह दो घंटे में यह काम कर आता है। इस तरह से दो कर्मचारी जाने से 200 रुपये का लॉस हो रहा है। इस तरह से 125 कर्मचारियों का डेली का तीन-चार लाख रुपये का लॉस है। इसी तरह हमारे लाईन लौसिज बढ़कर 31 प्रतिशत हो गये हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो बिजली विभाग की व्यवस्था असफल हुई है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसका सुधारीकरण करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो कर्मचारी अपनी डियूटी ठीक से नहीं करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा भी थोड़ा कसना चाहिए जिससे लाईन लोसिज़ दूर हो सकें। श्री सुर्जेवाला जी ने जो कुछ बताया है वह इनकी सरकार की कारगुजारी थी, क्योंकि बिजली के निजीकरण का मामला 1992 में इनकी सरकार के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन अब जब उस को सुधारीकरण के नाम से पढ़ते हैं तो ये उसका विरोध करते हैं, जो इनके लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही सरकार जो बिल पेश करने जा रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं बैठे हैं। कल इनसे हमने मिलने की कोशिश की थी। हमने उनसे कहा था कि विधायकों से सम्बन्धित एक बिल की मंजूरी दी गई है, यह बिल हम विधान सभा में लाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज की बैठक की सूची में देखा है कि इसमें उस बिल का जिक्र नहीं है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस सैशन में वह बिल जरूर लाया जाना चाहिए। हमारे साथ बहुत नाजायज बात हो रही है, बड़ी ज्यादती हो रही है। एक कलर्क भी हमारे से ज्यादा तनख्वाह लेता है।

श्री अध्यक्ष : आप यह सूचना कहां से लाए हैं ? हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री धर्मवीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है। उन्होंने कहा कि यह बात हाउस में कहना। हम बिल ले आएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बिल लाया जाना अति आवश्यक है। इस बारे में ट्रेजरी बैंचिज की भी कन्सैंट है और अपोजिशन बैंचिज की भी कन्सैंट है।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आप बैठिए। आपकी जेब में क्या है ? इस बात का मुझे क्या पता है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गाबा साहब ने जो बात कही है, उसके ऊपर कोई 6 महीने पहले चर्चा हुई थी। मुख्य मंत्री जी से सभी दलों के विधायक मिले थे इस तरह की चर्चा तो जरूर हुई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ था। अब इन्होंने यह बात कही है तो इस पर विचार किया जाएगा।

Mr. Speaker : Question is–

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is–

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is–

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is–

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause1

Mr. Speaker : Question is–

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is–

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is–

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that theBill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is–

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1997

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 1997. He will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1997. Sir, I also beg to move that–

The Haryana Appropriation (No. 2) bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Haryana Appropriation (No. 2) bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप पहले बोल चुके हैं इसलिए अब दिलू राम जी बोलेंगे।

श्री दिलू राम : स्पीकर साहब, आप पहले इनको बोल लेने दें, मैं अपने कागज ठीक कर लूं।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप तो बोल चुके हैं इसलिए अब सतविन्द्र सिंह जी बोलेंगे।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौंद) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्पीकर साहब, जब हविपा और भाजपा की गठबंधन सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अन्दर नशाबन्दी लागू की, उसका सभी ने स्वागत किया था। हमारे हरियाणा प्रान्त के लोग यह चाहते थे कि हमारे प्रदेश में शराब बंद हो। हरियाणा प्रान्त के लोग यह कहते थे कि चौधरी बंसी लाल जी जो कहते हैं, वह करते हैं। यह ठीक बात है कि शराबबंदी लागू करने से सरकार को 600 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान हुआ है लेकिन आज प्रदेश में शराब की तस्करी होने के कारण बहुत बुरा हाल है। हमारे प्रदेश के साथ लगते दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने अखबारों में यह बयान दिया है कि हमारा जो रेवेन्यू बढ़ा है, वह हरियाणा प्रान्त के बार्डर पर ठेके खोलने की वजह से बढ़ा है। हम हरियाणा के बार्डर पर अपने ठेके खोल कर वहां से रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं। हमारे विक्त मंत्री जी का टैलीविजन पर इन्टरव्यू था। उस इन्टरव्यू में उन्होंने शराब के बारे में बताया था। स्पीकर साहब, शराब के बारे में सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि हरियाणा प्रान्त में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से चाहे पुलिस की बात है, चाहे आम पब्लिक की बात है आज शरीफ आदमी उससे बहुत तंग है। कुछ दिन पहले की बात है हमारे ध्यान में वह बात लाई गई कि एक सरपंच के खेत में किसी आदमी ने शराब का एक ड्रम रख दिया और उस आदमी ने पुलिस में जा कर इतलाह दे दी कि फलां सरपंच के खेत में शराब निकल रही है। स्पीकर साहब, मजे की बात यह है कि जो कम्पलेनेन्ट था, उसी ने वह शराब का ड्रम वहां पर रखवाया था। जब वहां पर इस बारे में पंचायत हुई तो यह साबित हुआ कि वह शराब तो पार्टीबाजी की वजह से उस सरपंच को फंसाने के लिए वहां पर रखी गई थी। स्पीकर साहब, आज शराबबंदी लागू करने से हमारे टूरिस्ट कम्पलैक्सिज बंद पड़े हैं उनके अन्दर कोई यात्री नहीं ठहरता। शराबबंदी लागू होने से नए-नए क्राइम हो रहे हैं और स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवान बच्चे शराब की होम डिलिवरी कर रहे हैं जिन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्यों,क्योंकि जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने सरकार बनाने से पहले यह वायदा किया था कि हम हरेक बेरोजगार को गैस की एजेंसी देंगे, पैट्रोल पम्प देंगे और परमिट दिए जाएंगे। जो रेहड़ू लगाते हैं उनको भी परमिट दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन नौजवानों को कोई परमिट या कोई ऐजेंसी दी गई है ये रेहड़ू (जुगाड़) चलाने वालों को परमिट दिया गया है ? आज वे ही बेरोजगार शराब की तस्करी में शामिल हो गए हैं। अब उनको एक तरह से तो रोजगार मिल गया लेकिन यह जो रोजगार है, यह एक क्राइम का रोजगार है। इससे जो नई आने वाली पीढ़ी है जिसको हम सुधारना चाहते थे, सुधार नहीं रहे बल्कि बिगाड़ रहे हैं। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं जो सरकार ने घोषणा की थी कि शराब बंद की जायेगी, जिसका हमने स्वागत भी किया था। मैं बताना चाहता हूं कि आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर शराब की वजह से कांड न हुए हों। इस बारे में मैं ज्यादा न कहते हुए यह कहता हूं कि अगर सरकार इसे ईमानदारी से लागू करना चाहती है तो इसे लागू करे। मैं यह भी बात मानने के लिए तैयार हूं कि चौधरी बंसी लाल जी इसे सही अर्थों में बंद करना चाहते हैं मगर ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। (विघ्न) वह भी मैं बता देता हूं कि मेरे हल्के मुंडाल गांव में दो आदमी किसी के पास आये। उन्होंने उसको आकर कहा कि फलां आदमी धमकी दे रहा है, वह शराब का धंधा कर रहा है, जो शराब को निकालता है। पुलिस वालों को जब यह बात

पता लगी तो पुलिस कहने लगी कि उसको पकड़वा दो। इस पर वह कहने लगा कि पहले तो जब शराब निकलती थी तब तो चांदना हो जाता था, पकड़वा देते थे लेकिन अब तो शराब को निकालने का सिस्टम ही बदल गया है। अब शराब स्टोव पर कूकर के जरिये निकाली जाती है। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहतें हैं कि शराब बंदी अवश्य होनी चाहिए। यूं तो आज तक अफीम भी बंद नहीं हुई और 302 के मर्डर के केस भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस को सरकार ईमानदारी से लागू करे। अब लोग घरों में शराब बना रहे हैं। उसको रोका जाये। आज बहुत सारे लोग शराब निकालने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, जो लोग शराब निकालने का काम कर रहे हैं, उनके नाम आप बताना नहीं चाहते तो अकेले में पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर को बता दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात इनकी समझ में नहीं आती कि किसी प्वायंट पर बात कहते हुए ये अपनी बात कहते हैं तो जिस के बारे में यह कह रहे होते हैं उनका नाम नहीं बताते। या तो इनको नामों का पता नहीं है या पता है तो बता नहीं रहे। इनको चाहिए कि यदि नामों का पता है तो सदन में उनका नाम भी बताएं जो शराब का काम करते हैं। अगर नाम नहीं बताना चाहते तो इनको फिर सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : मैंने गांव का नाम बताया है। वहां पर एक आदमी की तीन बन्दूकें जब्त हुई हैं। राजौन्द थाने में यह केस दर्ज है और तीन बंदूकें बरामद हुई हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राणा साहब, आपकी बात ठीक है क्योंकि हरियाणा सरकार के नोटिस में यह बात ऑलरेडी है और केस थाने में रजिस्टर्ड है। अगर आप कंसर्ड लोगों के नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो उन्हें गुप्त ही रखें और बाद में आप इस बारे में सरकार को या कन्सर्न्ड मन्त्री को उन नामों की जानकारी दे देना।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये कहेंगे तो मैं हाउस में भी उनके नाम बता सकता हूं। ढाथरस गांव के 3-4 आदमी हैं। (विघ्न) सरपंच के भाई के खेत में ड्रम रखा। सरपंच का नाम बोधराज है और उसके भाई के खेत में ड्रम रखा। (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इन्होंने कन्सर्ड आदमी का नाम नहीं बताया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि मन्त्री महोदय बार-बार इन्टरवीन कर रहे हैं। राणा साहब एक नये सदस्य हैं उनको वे बार-बार इन्टरवीन करके बोलने नहीं दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। उस शरीफ आदमी के साथ जो हुआ है वह किसी भी शरीफ आदमी के साथ हो सकता है। यह एक गम्भीर विषय है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। पुलिस महकमा शरीफ लोगों को परेशान कर रहा है क्योंकि अब तो उनकी आमदनी एक दम कई गुणा बढ़ गई है। पहले तो उनको 100-200 रुपये ही मिला करते थे लेकिन अब तो 80-90 हज़ार रुपये उनको सीधे ही मिल जाते हैं जिससे वे खूब पैसा कमा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में कोई गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए। जो बात मैंने कही है वह बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग कहते हैं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था कुछ नहीं है लेकिन मैं इनकी सरकार के वक्त की बात बताना चाहता हूं। इनके राज में मन्त्री धमकियां दिया करते थे और दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया करते थे, थानों में बुलाकर लोगों को पिटवाया करते थे मैं स्वयं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में था और वे मन्त्री सोनीपत के थे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसी कारण छोटी-छोटी बात पर मन्त्री जी से मेरी अनबन रहती थी। उनको यह भी खतरा था कि अगर मैं उनके मुकाबले पर आ गया तो फिर मैं उन्हें कभी भी विधान सभा में नहीं आने दूंगा। (विघ्न)

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप इनसे कहें कि ये एप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलें (विघ्न एवं शोर)

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, अपनी सरकार के वक्त में इनको कानून-व्यवस्था दिखाई नहीं देती थी लेकिन आज ये लोग कानून-व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं जब कि उस वक्त कानून व्यवस्था कहीं थी ही नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खुद बताता हूं। सोनीपत में अपनी कीमत से लोगों ने पीने के पानी के लिए मकान के बाहर एक ट्यूबवैल लगवा लिया लेकिन मन्त्री महोदय को वह भी गंवारा नहीं हुआ। उन्होंने अफसरों को आदेश दे दिया कि उस ट्यूबवैल को उखड़वा दें, नहीं तो उनको बरखास्त कर देंगे। मुझे भी धमकाया गया कि अपने मकान में तुम रह नहीं सकोगे। साथ ही मुझे धमकी भी दी गई। ट्यूबवैल उखाड़ने के लिए महकमें के लोगों को भिजवा दिया। उस ट्यूबवैल को बचाने के लिए हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। यह ट्यूबवैल बचा। इस बारे में उस वक्त के मुख्यमंत्री भी जानते हैं। इस तरह की कानून व्यवस्था पिछली सरकार के वक्त में थी। पिछली सरकार के वक्त में मंत्री खुद धमकियां दिया करते थे और थाने बुलवाकर आदमियों को मरवाते थे। लेकिन आज हरियाणा में रात के बारह बजे हमारी बहनें और बेटियां गहने पहन कर जाती हैं और हाई-वे तक चली जाती हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनको कुछ बोल भी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी ये कहें कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं यह कहूंगा कि इससे पहले कानून व्यवस्था ही नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, इक्का दूक्का बात तो हो जाती है। लड़ाई-झगड़े होते हैं, मर्डर हो जाता है या बम्ब विस्फोट हो जाता है। लेकिन जो इनके वक्त में जान बूझकर करवाया जाता था, वह आज नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में 28-12-96 को दो बम विस्फोट हुए थे। उसमें 11 आदमी जख्मी हो गए थे लेकिन उनमें से तीन तो बहुत ही ज्यादा घायल हुए थे और उनके इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च आया था। उस वक्त के डी०सी० ने कहा था कि तुम्हें इलाज का पैसा हम देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उन तीन आदमियों को उनके इलाज का पैसा और कुछ कम्पनसेशन के रूप में दिया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अकरम खां (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज यहां पर कहा जाता है कि हरियाणा में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है जबकि ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में लॉ एंड आर्डर की स्थिति अच्छी है। आज इस सरकार ने जो शराब बंदी की है उससे हरियाणा सरकार को रैवेन्यू का नुकसान हुआ है। लेकिन यह जो शराब बंदी का कदम इन्होंने उठाया है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज यहां कहा जाता है कि हरियाणा में शराब बंद नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है आज हरियाणा में 80 प्रतिशत शराब बंद है और 20 प्रतिशत बंद नहीं है। यह भी बंद हो जाएगी। वैसे तो अफीम भी यहां पर बंद है लेकिन उसको भी बेचा जाता है। उसी तरह से शराब भी थोड़ी बहुत बेची जाती है। उसको भी बंद किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय,

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के हथनी कुंड बैराज का काम शुरू हुआ है। वहां पर जिन लोगों की जमीनें गवर्नमैंट ने ली हैं उनको उनकी जमीन के लिए सरकार अच्छा रेट दे और उनके परिवार में से एक आदमी को नौकरी दें। यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में टीचर्ज की काफी कमी है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा मानकपूर में जे०बी०टी० के लिए एक सैन्टर मंजूर किया गया है और पंचायत ने उसके लिए जमीन भी दे दी है। मैं चाहूंगा कि उसको जल्दी से शुरू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कनेसर से कालका तक हमारी फसलों को जंगली सूअर खराब करते हैं, जिस कारण फसलों का काफी नुक्सान होता है। उन सुअरों को मारने के लिए सरकार उनको परमिट दें जिससे फसलों का नुक्सान होना बंद हो जाए। हमारे इस सारे एरिया में सारी फसलें बरसात के पानी पर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर एम०आई०टी०सी० के ट्यूबवैल्ज लगाए जाने चाहिएं ताकि किसान इनके पानी से अपनी फसलें पैदा कर सकें। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि हमारे यहां पर जंगली सुअर काफी फसलों का नुक्सान करते हैं। तो इनके लिए भी परमिट्स दिए जाने चाहिएं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में जो फौरेस्ट डिपार्टमैंट ने पहले प्लांटेशन करवायी थी तो तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से प्लांटेशन करने वाले लोगों की मजदूरी नहीं दी गयी है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। छः या सात महीनों की उनकी पेमेंट बकाया पड़ी है। इसके अलावा मेरे हल्के में ममदूबास गांव है जो कि हिमाचल के बोर्डर के साथ लगता है उसमें आज तक भी पीने के पानी की लाईन नहीं पहुंची है और न ही वहां पर कोई सड़क जाती है। मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी ये समस्याएं भी दूर करें। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि हथनीकुंड बैराज बनाने के लिए जिन गरीब किसानों की जमीनें गयी हैं उनको सरकार को उनकी जमीनों की पूरी कीमत एवं नौकरी देनी चाहिएं। उन गरीब लोगों की बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन थीं लेकिन वे सब इस बैराज को बनाने में चली गयीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दें। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने का समय दें। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कितना टाईम बोलने के लिए दिया गया है। आप बजट पर भी बोल लिए और कल भी आप बीस मिनट बोले हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, बजट पर तो मैं बोला ही नहीं हूं।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, ये तो बाहर भी खड़े-खड़े बोलते ही रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पांच मिनट आप बोल लें और पांच मिनट दिलूराम जी बोल लेंगे। लेकिन पहले उनको बोलने दें।

श्री दिलूराम (गुहला, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो नशाबंदी लागू की है मैं ईमानदारी से इसके हक में हूं। लेकिन आज जो इसका नतीजा कुछ और आ रहा है मैं उसके बारे में सरकार को बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इलाका पंजाब के बोर्डर के साथ लगता है। सुमाना गांव जो कि पंजाब की एक सब डिवीजन है, में पिछली दफा डेढ़ करोड़ रुपये का शराब का ठेका हुआ था लेकिन इस बार वहां पर साढ़े पांच करोड़ रुपये का ठेका गया है। इसी तरह से नवां गांव में पिछली बार 70-

[श्री दिलू राम]

80 लाख रुपये का ठेका हुआ था लेकिन अब की बार चार करोड़ रुपये का ठेका हुआ है। यह भी मेरे हल्के के साथ लगता हुआ है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे हल्के के साथ लगते हुए पंजाब के इलाके में दस करोड़ रुपये का ठेका शराब का हुआ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर सरकार वास्तव में इस मामले को गंभीरता से लेती है तो उसको इन सरकारों से बात करनी चाहिए। वह क्यों नहीं पड़ौसी प्रदेशों की सरकारों से इस मामले में बात करती ? सरकार को उनसे कहना चाहिए कि कम से कम वे हरियाणा के साथ लगते चार या पांच किलोमीटर तक तो कोई ठेका न खोलें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जाने के लिए पहले बाया पंजाब होकर जाना पड़ता है और उसके बाद ही हम हरियाणा में गुजर सकते हैं। जहां उनके गांव हैं वहीं उनको ठेका खोलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कोई प्रावधान रखेंगे और उनके मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि कम से कम कुछ दूर तो ठेके होने चाहिए नहीं तो किस-किस आदमी को हम रोक सकते हैं ? स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा दूसरी यह गुजारिश करना चाहता हूं कि शामलात जमीन के बारे में कल यहां कम्यूनिस्टों ने बड़ा तगड़ा धरना दिया था। मेरे हल्के और सरदार जसविन्द्र सिंह जी के हल्के में ऐसी शामलात जमीन है। वहां पाकिस्तान से उजड़कर लोग आए थे और जंगल तोड़कर वे लोग वहां बसे थे। अब उनके दिमाग में यह डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कब उनको चौधरी बंसी लाल जी वहां से उठाकर बाहर कर दें। मैं चाहूंगा कि इस सरकार को कोई क्राइटेरिया फिक्स कर उस जमीन को उन लोगों को जो वहां 40-50 साल से रह रहे हैं, किश्तों पर अलौट करके दी जाएं ताकि वे अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण कर सकें। मेरे हल्के में सड़कों की जो दशा है, उसके बारे में मैं दो-तीन दफा कह चुका हूं। बार-बार कहना उचित नहीं होता। इसी प्रकार स्कूलों के बारे में भी मैंने कह दिया। एक सड़क के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि पेहवा से चीका की सड़क बड़ी अच्छी कारपेट हो रही थी और उस सड़क से जाने का मन करता था लेकिन जैसे ही यह कारपेट होते-होते गुहला सब-डिवीजन तक आई, उस पर ब्रेक लग गया। इस बारे पता किया तो कहते हैं कि फंड नहीं हैं। फंड क्या मेरे हल्के में आते ही खत्म हो गए ?

श्री अध्यक्ष : कौन से साल में और कौन से महीने में यह ब्रेक लगा है ?

श्री दिलू राम : सर, यह ब्रेक इसी साल जून महीने में लगा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इस चीज से यह शक नजर आता है कि जहां हविपा और भाजपा का विधायक नहीं है, उस हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : पेहवा से कौन विधायक है।

श्री दिलू राम : सर, पेहवा से सरदार जसविन्द्र सिंह जी हैं।

श्री अध्यक्ष : जब वहां सड़क बन रही है तो आपके साथ भेदभाव की क्या बात।

श्री दिलू राम : सर, जब मेरे हल्के में बन जाएगी तो भेदभाव वाली कोई बात नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। कल भी मैंने कहा था कि जब भी हमारी ओर से कोई प्रश्न पूछता है तो सत्ता पक्ष की ओर से यह जवाब आता है कि पहले की सरकार ने क्या किया। मैं तो इस बारे में यही कहूंगा कि पहली सरकार ने जो बोया था वह उन्होंने काट लिया लेकिन अब जो पौधा आप लगाएंगे उसका फल भी आपके सामने आ जाएगा। आपको यह कहना चाहिए कि यह कमी हम दूर करेंगे। फिर ये कहते हैं कि हमने गड्ढे खोदे। अगर हमने गड्ढे खोदे तो आपको यह कहना चाहिए कि हम बंद कर देंगे। अगर आप ये बातें करेंगे तो अगली बार हम आपकी जगह वहां होंगे और आप हमारी जगह बैठे होंगे। जनता जनार्दन किसी का वेट नहीं करती। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्हें दिन रात इधर बैठना नजर आता है। वहां बैठे-बैठे भी ये हमारी पार्टी के सदस्यों को किस तरह के लालच प्रलोभन देते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इन्हें दिन में सपने नहीं लेने चाहिए। इनकी पार्टी के नेता से जब झारखंड मुक्ति मोर्चे की बात करते हैं तो वे चले जाते हैं। स्पीकर सर, हरियाणा की जनता ने इनकी छुट्टी कर दी है क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार बन गई हम इनका वैलकम करते हैं। हम विरोध नहीं करेंगे। हम जनता जनार्दन को सब कुछ मानते हैं। जनता ने जो फैसला लिया है, ठीक लिया है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। (घंटी) आज जो आपने एम०एल०ए० होस्टल में कारपेंटिंग करवाई है, वार्निश करवाई है उसके लिए बड़ी मेहरबानी। लेकिन साथ ही आपने वहां खाना इतना महंगा कर दिया कि आम खाना 17 रुपये का है। उसके साथ अगर थोड़ा दही एक कटोरी मांग लें तो वह चार रुपये एवं यदि एक छोटी मक्खन की टिकी मांग लें तो वह दो रुपये की और लग जाती है (विघ्न) सुन तो लो मेरे हाथ में यह कटोरी है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर,

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, जाति को सामने न लायें सम्मानित मैम्बर के लिए ऐसे शब्द न कहें। मंत्री महोदय को कहें कि अपने शब्द वापस लें मेरी आपसे यह विनती है कि जो इन्होंने शब्द कहें हैं वे इसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी, पहले आप इनको बोलने दें फिर आप बोलना।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है सर। कांग्रेस पार्टी को खाने की पड़ी रहती है। यह पार्टी इस देश को खा गई है। कहीं बोफोर्स कांड, कहीं यूरिया कांड और कहीं झारखण्ड मुक्ति मोर्चा कांड और अब एम०एल०ए० होस्टल का खाना जो 17 रुपये का मिलता है उसके लिए इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। इनको तो खाने की प्रशंसा करनी चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय मंत्री पार्लिंधामेंटरी अफेयरस मंत्री है, इनको तो रूल्ज़ रेगूलेशन को फोलो करना चाहिये। ये ऐसी बातें न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी दिलूराम जी ने जो विषय छेड़ दिया है, उसके लिए मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले पांच साल से लगातार हम यह बात कहते रहे कि एम०एल०ए० होस्टल में सुधार हो लेकिन कप्तान अजय सिंह जो मेरे पड़ोसी हैं, अच्छे साथी हैं और उस समय वाई चांस मंत्री थे, मैंने इनको कई बार कहा कि होस्टल की तरफ भी देखो लेकिन इनके पास होस्टल जाने का समय नहीं था। आज चौधरी दिलूराम जी ने ठीक फरमाया कि थोड़े से समय में एक काया पलट हुई है। अगर कोई बात रह गई है, उसको भी पूरा किया जायेगा लेकिन जो कटोरी इनके हाथ में है यह होस्टल की नहीं है कहीं दूसरी जगह की है (विघ्न)

श्री दिलूराम : मैं कर्ण सिंह दलाल जी को एक बात कहना चाहूंगा कि * * * यहां नहीं होता (विघ्न) * * * इन्होंने देखा नहीं है, उसका इनको ज्ञान नहीं है। * * * तो भाई साहब पाकिस्तान में होता है यहां तो नाट का तमाशा होता है। ये बाजीगर * * * नहीं करते। स्पीकर सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन्होंने जो शब्द कहें हैं। उनको ये वापस लें। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष : जो दलाल साहब ने चौधरी दिलूराम के बारे शब्द कहे हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (विघ्न)

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरी हमेशा ही यह कोशिश होती है कि मैं कभी झूठ न बोलूं और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं। आप बात कर रहे हैं कि यह कटोरी एम०एल०ए० होस्टल की नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में ही यह कटोरी एम०एल०ए० होस्टल की है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महेदय मेरा प्वाएंट ऑफ आर्डर है। एक और गंभीर मुद्दा सदन के सामने आया है। इन्होंने बहुत कांडों में इस प्रदेश की जनता को लूटा है अब इनके कुछ और हाथ नहीं लग रहा है तो ये कटोरियां चुराने लगें हैं, इसलिए इन पर चोरी का मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : दिलू राम जी, अगर यह कटोरी होस्टल की है तो आप इसे यहां कैसे ले आए ?

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, यह कटोरी मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि यह सिकुड़ती जा रही है और इसके विपरीत खाने के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सिर्फ रेट ही न बढ़ाईए बल्कि इस कटोरी को भी बढ़ाईए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप डॉ कमला वर्मा जी को बोलने दें। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना। अब आप बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप हमेशा ही हमें बोलने नहीं देते हैं। हमें आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यही कारण है कि कल हम सदन में आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए।

श्री अध्यक्ष : विश्वास है या अविश्वास है, यह तो आपकी व्यक्तिगत बात है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 15 साल में पहली बार विपक्ष स्पीकर के खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, अब इनको बाहर जाना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य जो कि बहुत पुराने विधायक हैं और मंत्री होने का भी इनको अवसर मिला है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आज ये हैं, उसी पार्टी की सरकार के समय जब इनके आज के नेता मुख्यमंत्री थे, 1984 में भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जहां सुर्जेवाला जैसे वकील बैठे हों, जहां कैप्टन अजय सिंह जैसे माननीय सदस्य बैठे हों, उनकी तरफ से ऐसी बात हो जाए तो यह शोभा नहीं देता है। (विघ्न) मैं कैप्टन साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि वे विश्वास करें या न करें यह तो इनकी अपनी मर्जी है। कल 5 ऐसे आदमियों के उस अविश्वास प्रस्ताव पर साईन थे जो कि हाई कोर्ट में वकालत करते थे, जिनकी लम्बी स्टैंडिंग की वकालत रही है, उनको यह भी नहीं पता है कि स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चलो आपको हमारी भावना का तो पता चल गया है। विपक्ष की तरफ से आपके खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह तो कैप्टन साहब आपकी व्यक्तिगत बात है कि आप उस पर विश्वास करें या न करें। (शोर) I am not obliged to you. Take your seat and now you are not allowed to speak. Now, Dr. Kamla Verma will speak.

वाक आउट

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं। (इस समय माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव सदन से वाक आउट कर गए)।

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1997 (पुनरारम्भ)

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाई आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपने इनको बोलने के लिए काफी टाईम दिया फिर भी ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, इस आगस्त हाउस में बड़े-बड़े गम्भीर मसले आते हैं और इस आगस्ट हाउस में गम्भीर मसले आएं भी है। इस आगस्ट हाउस में चेयर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। स्पीकर साहब, 1966 से यह अगस्ट हाऊस इस जगह पर चल रहा है और उससे पहले यह दूसरी जगह चलता था। इस आगस्ट हाऊस में इस तरह के तीन अविश्वास प्रस्ताव आए। एक बार अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, वह रिजैक्ट हो गया। जो 1984 में चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस पर चर्चा हुई थी। स्पीकर साहब यह जो अविश्वास प्रस्ताव है that was not in order. कांस्टीच्यूशन की धारा 179 (सी) के तहत 14 दिन के नोटिस के बिना ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हां रिमूवल पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर साहब हमने आपकी अनुपस्थिति में आपका अभिनन्दन करते हुए यह बात कही कि आपने उस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करके इस सदन की गरिमा को और ऊंचा उठाया है आपने यह एक नई रिवायत और एक नई परम्परा डाली है। आपने कहा कि मैं इस महान सदन के सामने अपना सर झुकाता हूं क्योंकि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। वह अविश्वास प्रस्ताव आर्डरली नहीं था और वह संविधान की धारा 179 (सी) की शर्तों को भी पूरा नहीं करता था फिर भी आपने उसको स्वीकार किया। मैं अपने विरोधी पक्ष के भाईयों से कहना चाहूंगा कि आप कोई फर्जी बात कह करके इस सरकार की अलोचना करें तो फिर भी बात समझ में आती है। हमने इनसे आलोचना में इस तरह के आंकड़े मांगे तो ये वह आंकड़े नहीं दे सके। कह दिया कि वह आंकड़े तो मेरे दिल्ली वाले कुर्ते की जेब में रह गए। दिलू राम जी को आपने बोलने का समय दिया तो वे कहने लगे कि पहले मैं अपने कागज ठीक कर लूं फिर बोलूंगा। फिर भी आपने उनको बुलाया। स्पीकर सर, ये बार-बार हर सैटेंस पर खड़े हो जाते हैं। स्पीकर साहब, आपने अपनी उदारता दिखाई और उस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जबकि वह आर्डरली नहीं था। स्पीकर साहब, ये अपनी पुरानी आदत के अनुसार वैसे ही बात को हवा में उड़ा देते हैं। It does not appear good. आपने इनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या के हिसाब से जो बोलने का समय दिया, वह बहुत समय था इनकी पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा समय तक बोलें हैं अब जिस तरह से यह व्यवहार कर रहे हैं वह निन्दनीय है, ठीक नहीं है।

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ कमला वर्मा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में बोलते हुए मेरे कुछ विपक्ष के भाईयों ने मेरे विभाग के बारे में आलोचना की। विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला साहब सदन में नहीं हैं, मैं उनको जवाब देना चाहती थी लेकिन फिर भी मैं अब जवाब देती हूं ताकि उस बात का हरियाणा प्रान्त की जनता को पता लग जाए कि विपक्ष के नेता हरियाणा प्रान्त की जनता और इस सदन को किस प्रकार से गुमराह करते हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के काम कैसे होंगे क्योंकि बजट में उसके लिए केवल 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि प्लान स्कीम के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत जो ग्रांट दी जानी है, वह 19 करोड़ 54 लाख रुपये के लगभग है। ध्यान देने की बात यह है कि शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण के सुधार के लिए पिछले वर्ष 7 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान था और इस वर्ष 7 करोड़ 97 लाख रुपए का प्रावधान है। इसी प्रकार तदर्थ राजस्व योजना के तहत 123 लाख रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 136 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार छोटे व मध्यम नगर सुधार योजना के तहत पिछले वर्ष 75 लाख रुपये का प्रावधान था, उसके विरुद्ध इस वर्ष 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार 4 करोड़ 15 लाख रुपए और 3 करोड़ 65 लाख रुपए की ग्रांट हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से उपलब्ध करनी है जो स्वीकृत हो चुकी है। नॉन प्लान स्कीम में विकास कार्यों पर खर्च की जाने वाली ग्रांट 53 लाख रुपए से बढ़ा कर 55 लाख रुपए की है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को दी जाने वाली ग्रांट 25 लाख रुपये से 26 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न

13.00 बजे

नगरपालिकाओं/परिषदों एंव नगर निगमों की अपनी आय भी लगभग 150 करोड़ रुपए होनी है। इसके अतिरिक्त नेहरू रोजगार योजना के तहत भी लगभग 4 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल मिलाकर 173 करोड़ 54 लाख रुपये नगरपालिकाओं/परिषदों एवं नगर निगमों को विकास तथा अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर खर्च किए जाएंगे और बाकी विकास तथा अन्य भलाई के कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

यह अलग बात है कि विपक्ष के साथियों ने कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में इस मुद्दे को काफी उठाया। हमारे नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल अन-कंडीशनल विदड्रा कर ली। इसके बाद विपक्ष के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं रहा था। विपक्ष के पास दो ही मुद्दे थे जिनके तहत वह सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहती थी। एक मुद्दा कर्मचारियों की हड़ताल का और दूसरा मुद्दा गन्ने का मूल्य का था। हमारी सरकार ने समय रहते ही इन दोनों मुद्दों को खत्म कर दिया। कर्मचारियों ने अन कंडीशनल हड़ताल वापस ले ली और किसानों को गन्ने का पूरा भाव दे दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, धर्मवीर गाबा जी ने भी बोलते हुए कहा और शिकायत की कि नगर परिषद की कुछ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी नगर परिषद की भूमि जो जामा मस्जिद धमनूडन राय के साथ लगती है, यह नजूल भूमि है इसमें से 1350 वर्ग गज भूमि जो कि खसरा नं० 357/1 के अंतर्गत आती है, स्थानीय शासन विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की हुई है। पहले वहां प्राईमरी स्कूल चलता था, क्योंकि यह भूमि शिक्षा विभाग के पास ही है। इसका नगरपालिका से कोई वास्ता नहीं है। जब तक यह भूमि वापिस शिक्षा विभाग से नगरपालिका को स्थानांतरित नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछने पर पता चला है कि भूमि अब भी उनके पास ही है तथा इस पर किसी का नजायज कब्जा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते हुए यह बात भी आई कि श्रीमती कस्तूरी पत्नी ढल्लाराम का भवन मानचित्र जो कि 125 वर्ग गज भूमि पर निर्माण हेतु था, पालिका द्वारा पास किया गया। परन्तु इस संबंध में भवन निरीक्षक तथा पालिका अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में नहीं थी जिसके बारे कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में पालिका कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर गरीब आदमी को तंग किया जा रहा था क्योंकि कर्मचारियों द्वारा उठाये गए बिन्दुओं की संबंधित भूमि पर टाउन प्लानिंग स्कीम का निर्माण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस भूमि का रकबा केवल मात्र 125 वर्ग गज है इसलिए इस पर टाउन प्लानिंग स्कीम नहीं बनाई जा सकती क्योंकि किसी भी प्रकार की टी०पी० स्कीम कार्यान्वित करने हेतू विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है तथा इसके साथ-साथ अब टी०पी० स्कीम से संबंधित प्रावधान धारा 203 हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 को सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा डिलीट कर दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर किसी प्रकार का कोई अधिक्रमण नहीं है। भूमि का नक्शा बिल्डिंग बाए-लाज के अनुरूप है।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न नफे सिंह राठी जी ने उठाया था कि बहादुरगढ़ में नगरपालिका की कई करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। मैं बताना चाहूंगी कि 15-20 दिन पहले यह शिकायत आई थी। हमने उस शिकायत को उपायुक्त महोदय को जांच के लिए भेज दिया था। कोई अवैध कब्जे करे, हम ऐसा नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, दीवान जी ने एक बात कही कि जो अनअथोराईज्ड कालोनीज हैं और वे नगरपालिका की भूमि पर है तो उनको रैगुलराइज किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं उनको बताना चाहूंगी कि वह उस जगह का नक्शा पास करवाएं। यदि वह बिल्डिंग के बाई लाज के नाम पूरे करते होंगे तो वे उनको कमेटी की इलैक्टिड बोर्ड की जो एक सब कमेटी है, उससे उनके नक्शे पारित करवाये और फिर पार्षदों के माध्यम से उस स्कीम को उपायुक्त महोदय को एप्रूवल के लिए भेज दें। जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो सरकार एक मिनट की देरी लगाये बिना उनको एप्रूवल दे देगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर समाज कल्याण विभाग पर बोलते हुए भाई बलबीर सिंह जी ने कहा कि विकलांगों को हर वर्ष पैंशन लेने के लिए विकलांग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि ऐसा कोई विधान नहीं है कि उन्हें हर वर्ष विकलांग का सर्टिफिकेट लेना पड़े। एक बार प्रमाण-पत्र लेने के बाद पैंशन शुरू हो जाती है। एक बार पैंशन शुरू हो जाए तो वह काटी नहीं जाती है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पैंशन बुजुर्गों को दी जाती है। यह पैंशन 1987 में वृद्धों का सम्मान करते हुए दी जानी शुरू की गई थी। उस वक्त यह महसूस करते हुए यह पैंशन दी गई थी कि वृद्धों का सम्मान किया जाना चाहिए। उस वक्त इसका आधार आर्थिक नहीं था लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई। वर्ष 1990 से वृद्धावस्था पैंशन के लिए बुजुर्गों को आर्थिक आधार के साथ जोड़ा गया। इसमें कुछ शर्तें लगाई गईं जैसे एक तो वह हरियाणा का निवासी हो, और उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इसके साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई कि वह 100/-रुपये से अधिक पैंशन किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त न कर रहा हो। इस पैंशन को देने के लिए भी कई तरीके इस्तेमाल किए गये। पहले यह पैंशन मनीआर्डर के ज़रिये से देते रहे हैं। 1990-91 में 8 महीने यह पैंशन वृद्धों को नहीं दे पाए। इस सरकार ने आते ही यह नियम तय किया है कि पैंशन की राशि 7 तारीख तक हर वृद्ध को उसको घर दी जाएगी क्योंकि मनीआर्डर और पासबुक से पैंशन सही वक्त पर नहीं मिल पाती थी। स्पीकर सर, वृद्धावस्था पैंशन के बारे में स्थिति मैंने बता दी है। हर दो साल बाद इसके लिए फार्म भरे जाते हैं। विधवा पैंशन के बारे में एक बात आई कि क्लर्क या कोई सोशल वैल्फेयर ऑफिसर पैंशन काट देते हैं। अगर ऐसा कोई केस

[डॉ कमला वर्मा]

हमारे नोटिस में लाया जाता है तो उस पर तत्काल एक्शन होता है। अनिल विज जी ने बताया कि किसी की पैंशन काट दी जाती है। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसी अधिकारी या कलर्क को यह हक नहीं है कि वह किसी की पैंशन को काट दे अगर ये कोई स्पैसिफिक केस नोटिस में लाएं तो तत्काल एक्शन लिया जाएगा। रामफल कुण्डु ने नए फार्म भरे जाने के बारे में पूछा था। मैं उनको बताना चाहूंगी कि दो वर्ष के दौरान नए फार्म भरे जाते हैं। पैंशन स्वीकृत करने के लिए सोशल वैल्फेयर ऑफिसर के साथ एक डॉक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी होता है। वे जा कर वैरीफाई करते हैं। सर्वे हर दो साल के बाद होता है। पहले 1991 में फिर 1993 और 1995 में सर्वे हुआ और अब 1997 में सर्वे होगा। सारे पेपर्ज तैयार होने के बाद पैंशन जारी की जाती है। जो भी इलिजिबल लोग हैं उनको पैंशन अवश्य दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय सुर्जे वाला जी ने एक बात यह कही कि हरिजनों के लिए पैसा बहुत कम रखा गया है और हरिजनों को कुछ आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। इसके बारे में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। हरियाणा का वर्ष 1997-98 का कुल बजट 1575 करोड़ रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए मैं मानती हूं कि 27.22 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। मैं श्री सुरजेवाला को बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को लोगों के कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनके लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सब-काम्पोनैंट प्रोग्राम के माध्यम से भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके लिए निश्चित राशि निर्धारित नहीं होती है। भारत सरकार ने 20% अनुसूचित जातियों की संख्या के अनुपात में रेशो राशि रखी है और उनके विकास के लिए 19.75% राशि खर्च करने के दिशा निर्देश हैं। इसकी समीक्षा के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर एक सब-कमेटी गठित की जाती है फिर यह तय किया जाता है कि अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कितनी है। वर्ष 1985-86 में 6.18% का लक्ष्य रखा गया था। जोकि वर्ष 1996-97 में बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गया है। राज्य की कुल प्लान 1430 करोड़ रुपये में से 177.21 करोड़ रुपये इस मद के लिए रखे गए हैं। वर्ष 1997-98 की विशेष घटक योजना (एस०सी०पी०) के लक्ष्य अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निश्चित किए जाने हैं। यह प्रयास किया जाएगा कि वर्ष 1997-98 में भी योजना व्यय में कम से कम यह प्रतिशतता का यह लक्ष्य बनाकर रखा जाए।

यह ठीक है कि राज्य कि 1997-98 की कुल योजना 1575 करोड़ रुपये में से अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए केवल 27.22 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो कुल योजना का 1.72 प्रतिशत बनती है। इस बारे में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बजट व्यवस्था में प्लान, नान-प्लान तथा केन्द्रीय प्लान की क्रमशः 8.78 करोड़, 10.12 करोड़ तथा 8.32 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। वर्ष 1996-97 में भी जब राज्य का कुल योजना बजट 1430 करोड़ रुपये का रखा गया था, उस समय भी लगभग इसी प्रतिशतता पर विभाग को प्लान, नान-प्लान तथा केन्द्रीय प्लान में कुल 25.83 करोड़ रुपये अलाट किए गए थे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 1997-98 की राज्य प्लान में विभाग द्वारा 22.52 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा गया था परन्तु केवल 8.78 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग जो भी काम करना चाहते हैं हम उनको उस काम को करने के लिए जल्दी से जल्दी ऋण और अनुदान देने में सहायता करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो कह रही हैं वह गलत बात है। ये गलत स्टेटमैंट दे रही हैं।

वाक आउट

श्री अध्यक्ष : सुर्जेवाला जी आप बैठ जाएं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमें क्वैरिफिकेशन लेने के लिए भी समय नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण वाक-आउट कर गए।)

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1997 (पुनरास्थ)

Mr. Speaker : Question is–

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clauseby clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is–

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Charan Dass) ; Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow

*13.15 hours (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 20th March, 1997.)

28784—HVS—H.G.P., Chd.